www.rashtratak.com | twitter.com/rashtratak | facebook.com/rashtratak | @rashtratak

मूल्य ₹ 89

राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका

नई दिल्ली से प्रकाशित

राष्ट्र समाज

आपकी आवाज़...

RNI No.: DELHIN/2014/56304

वर्ष-13 ▪ अंक-06 ▪ सितंबर 2026 ▪ पृष्ठ संख्या 52

यूपीआई का स्वर्णिम दशक 12

जलप्रलय की भयावह तस्वीर 20

बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर

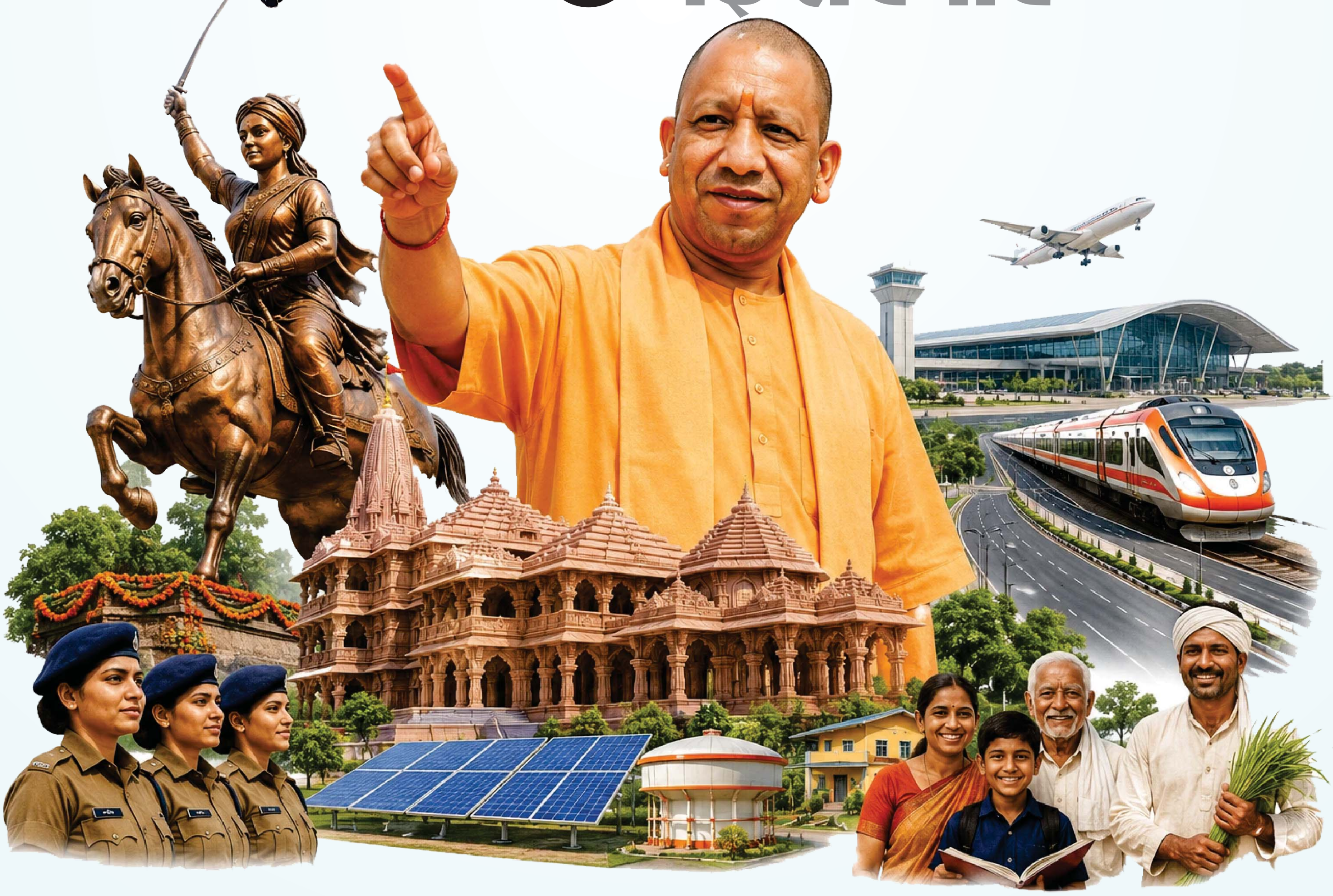

SAKARNI PLASTER (INDIA) PRIVATE LIMITED
D Mall 405, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
customercare@sakarni.com | +91-9810177365 | www.sakarni.com

संपादकीय

प्रमोद तिवारी संपादक

> भारतीय दंड विधि और दंड प्रक्रिया संहिता नागरिकों को हक देने के लिए बने कि अगर पुलिस किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार करे, तो उसे 24 घंटे में शहर के मजिस्ट्रेट के सामने लाए और तब मजिस्ट्रेट तथ्यों की ऊपरी जांचपड़ताल करने के बाद ही कैद में रखने की इजाजत दे।

आम आदमी की स्वतंत्रता

कानूनों की आड़ में आम आदमी की स्वतंत्रता छीनने की आदत सरकार में इतनी बुरी तरह फैली हुई है कि अंगरेजों के समय जो कानून नागरिकों के बचाव के लिए बने थे, उन्हें वह तोड़मरोड़ कर जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अंग्रेजों से पहले इस देश में जंगलराज था चाहे वह हिंदू राजाओं का समय रहा हो या मुसलिम राजाओं का। कोतवाल जब चाहे, जिसे चाहे बंदी बना सकता था। राजा जब चाहे जिसे चाहे अंधेरी कोठरी में डाल सकता था। भारतीय दंड विधि और दंड प्रक्रिया संहिता नागरिकों को हक देने के लिए बने कि अगर पुलिस किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार करे, तो उसे 24 घंटे में शहर के मजिस्ट्रेट के सामने लाए और तब मजिस्ट्रेट तथ्यों की ऊपरी जांचपड़ताल करने के बाद ही कैद में रखने की इजाजत दे। इस नियम का धीरे-धीरे जमकर दुरुपयोग होने लगा। प्रशासन, पोलिटिशियन और पुलिस के दबाव में मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत पर छोड़ते ही नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक औरत के धरने आदि के बनाए गए एक वीडियो पर मानहानि और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्रशांत कनौजिया नामक पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट ने जमानत नहीं दी कि जांच चल रही है। यह कैसी जांच थी कि आरोपी को जेल में रहना पड़े? मजिस्ट्रेट न संविधान की भावना सुनते हैं न कानून के शब्दों को देखते हैं। लगभग मशीनी तरह से वे पुलिस का साथ दे कर जेल भेजने में जल्दबाजी दिखाते हैं। कई बार तो बंद आरोपी को वकील का इंतजाम करने का समय तक नहीं मिलता।

मजिस्ट्रेटों में न्याय की जगह अन्याय करने की शक्ति कहां से आती है, दरअसल, ऊपर तक की सरकारें इन को शह देती हैं कि नागरिकों को कुचलो, दबाओ, बंद करो, संविधान की हत्या करो। उत्तर प्रदेश के उक्त मामले में प्रशांत का केस जब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बजाय नागरिक के पक्ष में खड़े होने के, नागरिक के संवैधानिक हितों की रक्षा करने के, संवैधानिक हक वाले अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल कहते रहे कि मामला तो पहले से मजिस्ट्रेट के पास है, अगर छूट चाहिए तो अपील करने के लिए सैशन कोर्ट जाओ, फिर हाईकोर्ट, फिर डिवीजन बैंच और उस के बाद यहां सुप्रीम कोर्ट। यानी, तब तक जेल में सड़ो। जब सर्वोच्च न्याय अधिकारी इस तरह की बात करेंगे तो निचले दर्जे के मजिस्ट्रेट डरेंगे ही। वे पुलिस की सुनेंगे, पुलिस के सामने खड़े होने की हिम्मत न रखेंगे, चाहे इस दौरान नागरिक सड़ता रहे और 2-4 साल बाद बेगुनाह ही पाया जाए। यह गनीमत है कि न्यायपालिका ने सरकार से जज नियुक्त करने का हक अब छीन लिया है। हां, पुलिस रिपोर्ट तो वही पुलिस आज भी बनाती है जो किसी को भी पकड़ कर मजिस्ट्रेट या जज के सामने खड़ा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले में नागरिक को तुरंत राहत दी, यह संतोष की बात है, पर यदि साथ में निचली अदालत के मजिस्ट्रेट का तबादला भी कर देती, तो शायद ज्यादा अच्छा होता।

राष्ट्र समाज

RNI No.: DELHIN/2014/56304 ₹ 89

वर्ष-13, अंक-06, सितंबर 2026

पृष्ठ संख्या-52

प्रेरणा स्रोत
स्व.पुरुषोत्तम तिवारी, स्व.एन.के. लोहिया

मुख्य संरक्षक
विनीत कुमार गुप्ता

संरक्षक
बालमुकुन्द ओझा, त्रिवेणी नाथ तिवारी, हरिशंकर दुबे, संजीव गोयल

संपादक
प्रमोद तिवारी

सह संपादक
सुशील ओझा,आनंद दीप श्रीवास्तव, आचार्य श्रीकांत तिवारी

सलाहकार समिति
अशोक गुप्ता (सकरनी) सभाजीत पांडेय, एम. के त्रिपाठी, विपिन गोयल, संजीव गोयल, ऋषि मित्तल

कानूनी सलाहकार
अधिवक्ता बीपी पाण्डेय, गौरव भारद्वाज

ब्यूरो चीफ
किरन ओझा, पुनीत मिश्र, अखिलेश शर्मा, बसंत भट्ट, हरीश तिवारी, अशोक शर्मा

प्रसार
पुनीत मिश्रा-9911882767

विज्ञापन
आशुतोष तिवारी- 83682 72439

डिजाइन व प्रोडक्शन
एनएम मीडिया सॉल्यूशंस, दिल्ली

संपादकीय कार्यालय: मकान नं. 2,पहली मंजिल, पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

दूरभाष: 011-40105158, 9953772767
वेब : www.railhumrahi.com

ई-मेल : rastrasamaj@gmail.com

स्वत्वाधिकारी अपराइट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक प्रमोद तिवारी द्वारा एस-561, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-2, नई दिल्ली-84 से प्रकाशित तथा मित्तल इण्टरप्राइजेज 2016 गोकुल शाह स्ट्रीट सीता राम बाजार दिल्ली-06 से मुद्रित।

***संपादक: प्रमोद तिवारी ***

लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है, तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय में ही किया जायेगा। राष्ट्र समाज पत्रिका में प्रकाशित सभी पद अवैतनिक हैं। पत्रिका के लिए भेजी गयी सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व अनुबंध के बिना कोई भी पारिश्रमिक देने की व्यवस्था नहीं है।

06

बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अब केवल एक राजनीतिक...

12

चीनी की मिठास पर महंगाई...
वैश्विक स्तरपर इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में दुनियां एक ऐसे दौर से गुजर रही है,जहां ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन तीनों ...

14

यूपीआई का स्वर्णिम दशक
एक समय था जब छोटी-सी खरीदारी के लिए भी जेब में नकद रखना जरूरी माना जाता था। सब्जी खरीदनी हो, चाय पीनी हो, किराने का सामान लेना हो या ...

अंदर

18

22

नितिन नवीन की नई टीम : नई ऊर्जा और नया संतुलन
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के साथ यह संकेत दे दिया है कि भाजपा अब संगठन को केवल पदों के पुनर्विन्यास के रूप में नहीं, ...

जलप्रलय की भयावह तस्वीर
नेपाल इस समय आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक त्रासदियों में से एक से जूझ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल-चीन सीमा के निकट..

49

दीया मिर्जा का छलका दर्द
बॉलीवुड अभिनत्री दीया मिर्जा सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि स्टाइल आउकॉन भी हैं। दीया मिर्जा के लुक्स और उनकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी है।...

बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर

योगी मॉडल

कानून-व्यवस्था से लेकर निवेश तक, किसान से लेकर युवा तक, नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने की कोशिश

@ प्रमोद तिवारी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अब केवल एक राजनीतिक चेहरे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल के साथ जुड़ चुका है, जिसमें कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, निवेश, रोजगार, किसान कल्याण और धार्मिक पर्यटन को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई देती है। वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, तब राज्य के सामने विकास के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर भी बड़ी चुनौतियां थीं।

आज लगभग एक दशक बाद सरकार अपने कामकाज को निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक गलियारों, डिजिटल प्रशासन व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक बदले हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर दिखाई देता हो, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं और चुनावी तैयारियों को गति दी है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर योगी सरकार अपने पक्ष में किस काम और किस मॉडल को सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करेगी। इसका उत्तर कई स्तरों पर दिखाई देता है।

कानून-व्यवस्था बड़ी पहचान

योगी सरकार की सबसे प्रमुख पहचान कानून-व्यवस्था को लेकर बनी है। सरकार ने शुरूआत से ही अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं में रखा। पुलिस व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल, कमिश्नरेट प्रणाली के विस्तार, साइबर पुलिसिंग और आधुनिक फॉरेंसिक सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्य सरकार के अनुसार, प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन और पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। फॉरेंसिक साइंस लैब, स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया गया है।

इस बदलाव का असर केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं माना जा सकता। कानून-व्यवस्था का सीधा संबंध निवेश, व्यापार, पर्यटन और आम नागरिक के भरोसे से है। यदि किसी प्रदेश में कारोबारी अपने व्यवसाय को सुरक्षित महसूस करता है, महिला बिना भय के सार्वजनिक स्थानों पर जा सकती है और आम नागरिक प्रशासन से सहायता की उम्मीद कर सकता है, तो यह आर्थिक गतिविधियों के लिए भी सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। यही कारण है कि योगी सरकार के लिए कानून-व्यवस्था महज राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि विकास की बुनियादी शर्त के रूप में सामने आती है।

एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। ऐसे प्रदेश में विकास के लिए सड़क, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और औद्योगिक कनेक्टिविटी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। योगी सरकार के कार्यकाल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को विकास की रणनीति का प्रमुख हिस्सा बनाया गया।

राज्य सरकार के अनुसार, देश के

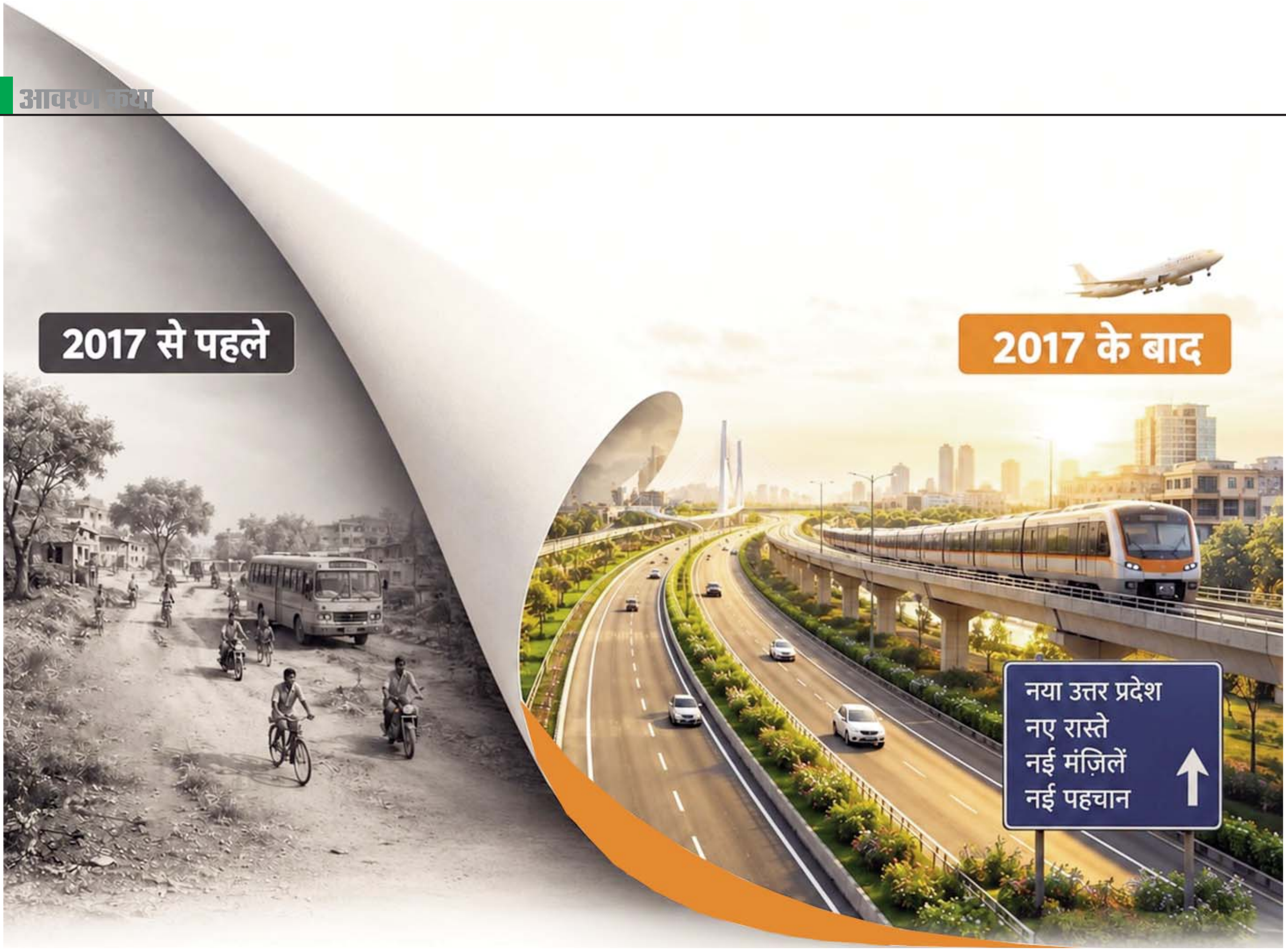

एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 55 प्रतिशत है और गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद यह हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। यह केवल सड़क निर्माण का आंकड़ा नहीं है। बेहतर कनेक्टिविटी का अर्थ है—किसान की उपज का बाजार तक जल्दी पहुंचना, उद्योगों के लिए माल ढुलाई आसान होना, छोटे शहरों का बड़े आर्थिक केंद्रों से जुड़ना और पर्यटन को गति मिलना।

इसी कड़ी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक सड़क तथा औद्योगिक कनेक्टिविटी का विस्तार राज्य के विकास को अधिक संतुलित बनाने की कोशिश भी है।

प्रशासनिक नजरिया

किसी भी राज्य की आर्थिक ताकत केवल सरकारी खर्च से नहीं बनती। निजी निवेश, उद्योग, एमएसएमई और रोजगार इसके महत्वपूर्ण आधार हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने पर विशेष जोर दिया है। सरकार के निवेश पोर्टल के अनुसार, उत्तर प्रदेश में हजारों निवेश समझौते दर्ज किए गए हैं और निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निवेश सारथी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। यह प्लेटफॉर्म निवेशक को इंटेंट से लेकर एमओयू, प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग और शिकायत निवारण तक डिजिटल सुविधा देने के लिए बनाया गया है।

राज्य में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इस बदलती औद्योगिक सोच का उदाहरण है। आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ को इससे जोड़ा गया है। सरकार के अनुसार, कॉरिडोर से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश और करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसरों की संभावना है।

2026 में डेटा सेंटर नीति, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी इसी दिशा का विस्तार हैं। नई डेटा सेंटर नीति में भूमि सब्सिडी, बिजली शुल्क में छूट और एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। यह संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ डिजिटल और तकनीकी अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश हो रही है।

नौकरी से उद्यमिता तक

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। लेकिन इतनी बड़ी युवा आबादी को रोजगार और अवसर देना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में भी शामिल है। योगी सरकार ने सरकारी भर्ती में पारदर्शिता, कौशल विकास और उद्यमिता को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। राज्य सरकार के नौ वर्ष के उपलब्धि दस्तावेज के अनुसार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र तथा एमएसएमई के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों का दावा किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के माध्यम से युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की गई है।

यहां एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। युवा को केवल नौकरी तलाशने वाला बनाने के बजाय उसे उद्यमी बनाने की सोच पर जोर दिया जा रहा है। यदि कोई युवा अपना छोटा उद्योग, सर्विस सेंटर, स्टार्टअप या स्थानीय व्यवसाय शुरू करता है तो वह स्वयं के साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता है। इसी सोच के कारण टरटए और स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश की आर्थिक रणनीति

में महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

अर्थव्यवस्था पर फोकस

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व आज भी बहुत बड़ा है। इसलिए किसी भी सरकार के लिए किसान की आय, कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना केंद्रीय मुद्दा होना स्वाभाविक है। राज्य सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, आम और दुग्ध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों के खातों में लगभग 99 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित होने का दावा किया गया है। गन्ना किसानों को भी बड़ी मात्रा में भुगतान किया गया है।सरकार के अनुसार, राज्य में कृषि विकास दर में भी वृद्धि हुई है और मंडी शुल्क को पहले की तुलना में कम किया गया है। किसान के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। बाजार, भंडारण, प्रसंस्करण और बेहतर परिवहन भी उतने ही जरूरी हैं। इसी कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों से जोड़ने की कोशिश महत्वपूर्ण हो जाती है।

महिला आत्मनिर्भरता तक

योगी सरकार की योजनाओं में महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी दोनों को प्राथमिकता दी गई है। मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखा गया है। राज्य सरकार के अनुसार, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में मिशन शक्ति केंद्रों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक सहायता उपलब्ध कराना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों, छोटे व्यवसायों और स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना भी इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में यदि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो उसका असर सीधे परिवार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

पर्यटन का नया अध्याय

उत्तर प्रदेश के पास धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की असाधारण संभावनाएं हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, विंध्याचल और कुशीनगर जैसे स्थान केवल धार्मिक महत्व नहीं रखते, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़े अवसर पैदा करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के अनुसार, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने यात्रा की। इतने बड़े पर्यटन आंकड़े का अर्थ है होटल, परिवहन, रेस्तरां, हस्तशिल्प, फूल, प्रसाद, स्थानीय उत्पाद और छोटे व्यवसायों के लिए बढ़ते अवसर। यही कारण है कि योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को केवल आस्था से नहीं बल्कि रोजगार और स्थानीय आर्थिक विकास से जोड़कर देख रही है।

कामकाज में डिजिटल बदलाव

योगी सरकार के दौर में प्रशासन को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया है। भूमि रिकॉर्ड, निवेश, शिकायत निवारण, पुलिसिंग और विभिन्न सरकारी सेवाओं में तकनीक के इस्तेमाल ने प्रशासन को अधिक डेटा आधारित बनाने की कोशिश की है। निवेश के क्षेत्र में 50 से अधिक विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की व्यवस्था इसका उदाहरण है। 2026 में एआई, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई नीतियां यह बताती हैं कि सरकार अब केवल पारंपरिक विकास परियोजनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उत्तर प्रदेश को नई तकनीकी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की कोशिश की जा रही है।

प्रशासन की जवाबदेही

किसी भी सरकार की वास्तविक परीक्षा उसके बड़े प्रोजेक्टों से ज्यादा इस बात से होती है कि सामान्य नागरिक को सरकारी कार्यालयों में कितनी आसानी से सेवा मिलती है। योगी सरकार के सामने अभी भी चुनौतियां कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधतापूर्ण प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, शहरी

दबाव, प्रदूषण, ग्रामीण आय और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान लगातार काम मांगता है।

यही कारण है कि योगी मॉडल को केवल उपलब्धियों के आंकड़ों से नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में इन चुनौतियों से निपटने की क्षमता से भी परखा जाएगा। लेकिन यह भी तथ्य है कि सरकार ने विकास के कई क्षेत्रों को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मार्च 2026 में सरकार ने अपने नौ वर्षों के कामकाज को नौ प्रमुख विषयों, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, निवेश, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्रों–के माध्यम से सामने रखा था।

2027 की चुनौती

अब नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव शुरू कर दिए हैं। जून 2026 में प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ, जिसमें नए पदाधिकारियों और क्षेत्रीय जिम्मेदारियों का विस्तार किया गया। हालिया राजनीतिक संकेतों में भाजपा की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का प्रमुख चेहरा होंगे और विकास को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा।

लेकिन चुनाव किसी भी सरकार के लिए केवल उपलब्धियों की सूची प्रस्तुत करने का अवसर नहीं होता। जनता अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेती है। योगी सरकार के सामने इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि पिछले वर्षों में शुरू हुई योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा है। रोजगार के आंकड़े जमीन पर कितने अवसरों में बदलते हैं, निवेश कितने नए उद्योगों में बदलता है, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचाते हैं और किसान तथा छोटे व्यापारी अपने जीवन में कितना बदलाव महसूस करते हैं, इन सवालों के जवाब महत्वपूर्ण होंगे।

योगी मॉडल की असली तस्वीर

उत्तर प्रदेश को बदलना आसान काम नहीं है। लगभग 24 करोड़ की आबादी, विशाल भौगोलिक क्षेत्र, अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियां और क्षेत्रीय असमानताएं किसी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश करती हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश की कहानी को केवल राजनीति के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह कहानी एक ऐसे राज्य की भी है जो अपनी पुरानी पहचान के साथ नई आर्थिक और तकनीकी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है।

एक तरफ अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक केंद्र हैं, तो दूसरी तरफ डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आधुनिक परियोजनाएं। एक तरफ किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी तरफ स्टार्टअप और एमएसएमई एक तरफ महिला सुरक्षा है, तो दूसरी तरफ महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता।

एक तरफ एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट हैं, तो दूसरी तरफ गांवों को बाजार से जोड़ने की कोशिश। यही विविधता योगी सरकार के मॉडल को व्यापक बनाती है। राजनीति में सरकारों का मूल्यांकन अंततः जनता करती है। उपलब्धियां सरकार बताती है, लेकिन उनका प्रभाव नागरिक महसूस करता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले वर्षों में जिस विकास मॉडल को आगे बढ़ाया गया है, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी इसी कसौटी पर होगी।

फिलहाल तस्वीर यह है कि उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए एक स्पष्ट दिशा तय करने की कोशिश की है, मजबूत कानून-व्यवस्था, तेज इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आधुनिक तकनीक। 2027 की राजनीतिक लड़ाई इसी सवाल पर केंद्रित हो सकती है कि क्या यह मॉडल उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने भविष्य के लिए पर्याप्त भरोसा देता है।

BTW

Delivering Taste, Quality & Legacy

AT EVERY STEP

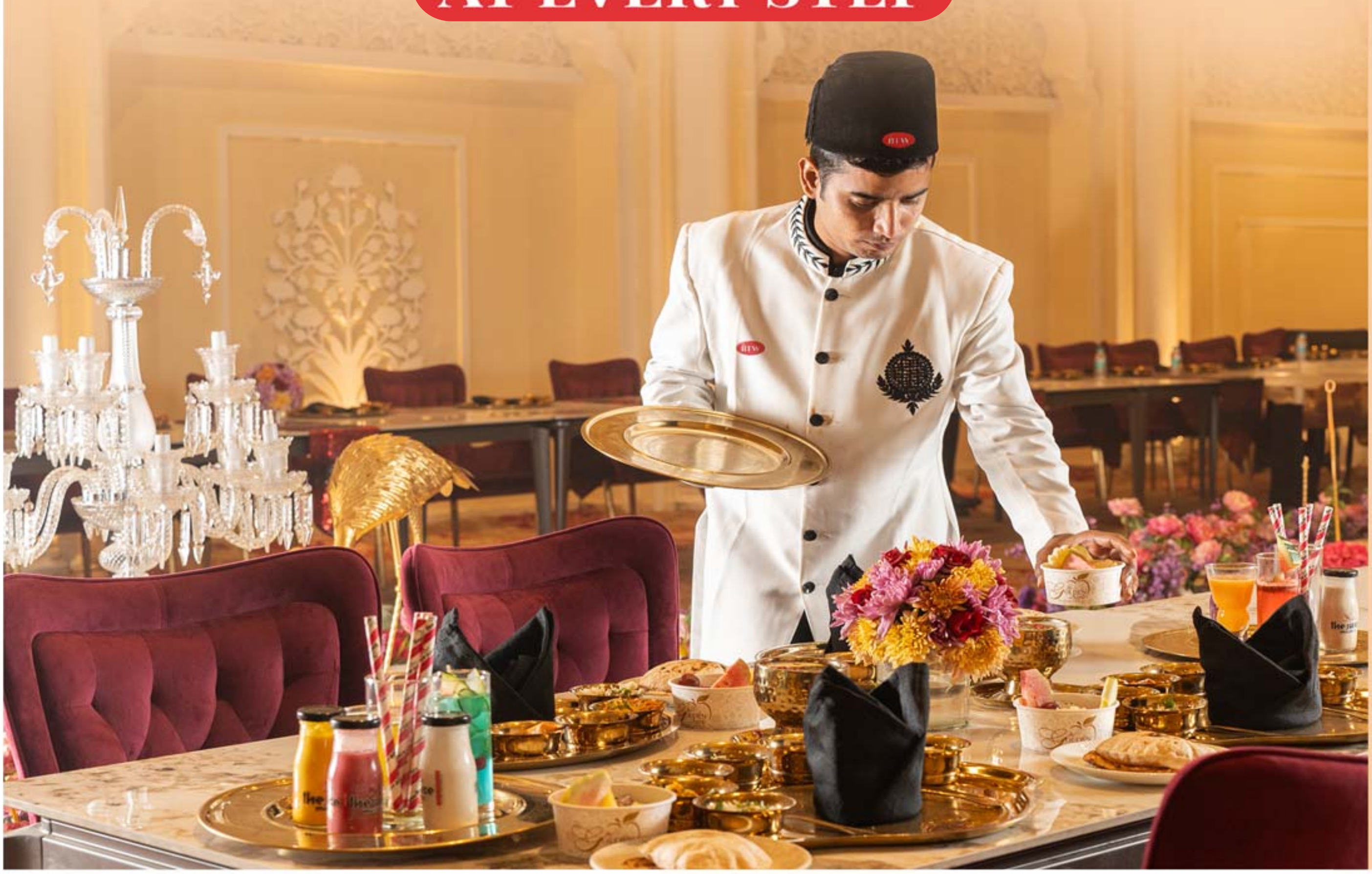

RETAIL

As a pure vegetarian restaurant, we serve a wide variety of multi-cuisine dishes and are especially known for our chaat and snacks. We operate 20 QSR outlets across Delhi NCR and Mohali. Our stores also offer a comprehensive selection of sweets and gifting options.

FMCG

Our FMCG range has over 1000 SKUs, available across major modern outlets, e-commerce platforms, army canteens, and police canteens. We also manufacture material for several esteemed brands through private labelling, like Unibic, Big Basket, Vishal Mega Mart etc.

CATERING

We are one of India's largest Chaat caterers and offer catering services across the globe. On average, we serve around 75 functions each wedding season, maintaining our quality and legacy at every event.

For More Information

01164646464 | customercare@btwindia.com | www.btwindia.com

चीनी की मिठास पर महंगाई का वार

@ किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में दुनियां एक ऐसे दौर से गुजर रही है,जहां ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन तीनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़ चुके हैं। पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना,कार्बन उत्सर्जन घटाना और घरेलू ऊर्जा संसाधनों का विस्तार करना आज भारत सहित हर बड़ी अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता है। इसी व्यापक रणनीति के तहत भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एथनोल सप्लाई ईयर 2024-25 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 19.24 प्रतिशत तक पहुंच चुका था और 2025-26 के लिए 20 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। एथेनॉल उत्पादन क्षमता भी अक्टूबर 2025 तक बढ़कर लगभग 1,953 करोड़ लीटर हो चुकी थी। लेकिन अगस्त 2026 में चीनी की कीमतों में आई असाधारण तेजी ने इस नीति के दूसरे पहलू पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, क्या ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दौड़ में कहीं भारत कीखाद्य सुरक्षा और आम उपभोक्ता की रसोई तो महंगी नहीं हो रही?

यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसा विशाल और घनी आबादी वाला देश खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के मामले में किसी भी प्रकार का जोखिम लंबे समय तक वहन नहीं कर सकता। ऊर्जा और भोजन दोनों आवश्यकताएं हैं, लेकिन प्राथमिकता के स्तर पर भोजन जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि किसी नीति के कारण ईंधन सस्ता, आयात बिल कम और पर्यावरणीय लाभ बेहतर होते हैं,लेकिन उसी प्रक्रिया में रोजमर्रा की खाद्य सामग्री महंगी होने लगती है, तो नीति की सफलता को केवल ऊर्जा के आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। उसे किसान,उद्योग, उपभोक्ता,महंगाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा,सभी कसौटियों पर परखना होगा। चीनी का बाजार बहुआयामी परीक्षा के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है।

साथियों,अगस्त 2026 इस चिंता को और गंभीर बनाता हैं। चीनी की कीमतें पिछले महीनों में तेजी से बढ़ी हैं और सरकार को घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए असाधारण कदम उठाने पड़े हैं। 20 अगस्त को केंद्र ने एक दशक में पहली बार 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी,जिसका उद्देश्य घरेलू उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों पर दबाव कम करना है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो महीनों में घरेलू चीनी कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।सरकार ने इससे पहले निर्यात पर रोक और स्टॉक-सीमा जैसे कदम भी उठाए थे।इसका अर्थ स्पष्ट है कि समस्या केवल किसी एक व्यापारी,किसी एक राज्य या किसी एक दिन की कीमत वृद्धि नहीं है; देश के चीनी आपूर्ति तंत्र में वास्तविक दबाव पैदा हुआ है।मेरी अपनी राइस सिटी गोंदिया में पिछले लगभग 20 दिनों से चीनी के खुदरा भाव पर नजर रखने के दौरान शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को लगभग 70 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव बताया गया। यदि यह स्थानीय खुदरा बाजार का वास्तविक लेन-देन मूल्य है, तो लगभग 20 दिनों में 45 रुपये के आसपास के स्तर से 70 रुपये तक पहुंचना करीब 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि है। इसे राष्ट्रीय औसत मानना उचित नहीं होगा,क्योंकि अलग-अलग शहरों में थोक, खुदरा, ब्रांड, गुणवत्ता, परिवहन और स्थानीय आपूर्ति के कारण कीमतें अलग हो सकती हैं। फिर भी गोंदिया का यह अनुभव उस राष्ट्रीय मूल्य-दबाव की स्थानीय तस्वीर अवश्य प्रस्तुत करता है जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय बाजार में तेजी से भी होती है। मुंबई में भी

हाल में चीनी के भाव में एक सप्ताह में लगभग 8 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। यह अकेले ई-20 की कीमत नहीं है; इसमें उत्पादन की कमी, मौसम, कम शुरूआती स्टॉक, त्योहारी मांग, व्यापारिक अपेक्षाएं, परिवहन, स्थानीय मार्जिन और संभव जमाखोरी जैसे कई तत्व शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि संकट बहु-कारकीय है। सरकार का 10 लाख टन शुल्क- मुक्त आयात का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई है। इसलिए गोंदिया में 70 रुपये का भाव यदि लगातार कई दुकानों और अलग-अलग लेन-देन में मिल रहा है, इसे स्थानीय आपूर्ति-श्रृंखला में असामान्य तनाव का सटीकता से संकेत माना जाना चाहिए।

साथियों,सबसे पहले भारत का चीनी नियामक ढांचा भी इस संकट को समझने में महत्वपूर्ण है। चीनी और गन्ना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट,1955 के दायरे में आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार शुगरकेन (कंट्रोल) आर्डर ,1966 के तहत सरकार गन्ने के एफआरपी सहित कई पहलुओं को नियंत्रित करती है, जबकि शुगर (कंट्रोल) आर्डर 2025 उत्पादन, बिक्री, स्टॉक, आयात -निर्यात और न्यूनतम बिक्री मूल्य जैसे विषयों पर सरकार को नियामक शक्तियां देता है।इसलिए चीनी को पूरी तरह मुक्त बाजार की वस्तु समझना सही नहीं होगा। यह ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार किसान, मिल, व्यापारी और उपभोक्ता के बीच संतुलन बनाने के लिए लगातार हस्तक्षेप करती है।यही कारण है कि चीनी की कीमत बढ़ने का असर केवल उपभोक्ता की चाय तक सीमित नहीं रहता।मिठाई उद्योग, बिस्कुट, बेकरी,शीतल पेय, आइसक्रीम होटल-रेस्तरां और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की लागत बढ़ती है। अंततः इसका कुछ हिस्सा उपभोक्ता तक पहुंचता है और व्यापक खाद्य महंगाई को प्रभावित कर सकता है।

दूसरी ओर, यदि चीनी की कीमत बहुत कम रखी जाती है तो मिलों की नकदी स्थिति कमजोर हो सकती है और किसानों के गन्ना भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती चीनी सस्ती करो जितनी सरल नहीं है;उसे किसान को उचित मूल्य, मिल को आर्थिक स्थिरता और उपभोक्ता को वहनीय कीमत,तीनों उपलब्ध कराने हैं।

साथियों, इस परिस्थिति को केवल एथेनॉल बनाम चीन के सरल समीकरण से समझना अधूरा होगा। वास्तव में भारतीय चीनी अर्थव्यवस्था गन्ना, चीनी, शीरा, एथेनॉल, किसान भुगतान, मिलों की नकदी स्थिति, सरकारी कोटा, निर्यात-आयात, मौसम और त्योहारों की मांग—इन सभी के बीच बनी एक जटिल आर्थिक श्रृंखला है। एथेनॉल इस श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा अवश्य है, लेकिन वही अकेला कारण नहीं है। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है।गन्ने से चीनी और एथेनॉल बनने की प्रक्रिया को समझना यहां जरूरी है। गन्ने से चीनी बनाने के बाद अलग-अलग प्रकार के शीरे प्राप्त होते हैं। सी-हैवी मोलासेज मुख्यतः चीनी निर्माण की अंतिम अवस्था का उप-उत्पाद है, जबकि बी झ हैवी मोलासेज में अधिक सुक्रोज रहता है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए बी झ हैवी मोलासेज , गन्ने के रस, सिरप और यहां तक कि चीनी-आधारित फीडस्टॉक से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। आधिकारिक नीति के अनुसार 2024-25 में गन्ने के रस/चीनी/ शुगर सिरप से बने एथेनॉल का एक्स-मिल मूल्य 65.61 रुपये प्रति लीटर और बी-हैवी मोलासेज आधारित एथेनॉल का 60.73 रुपये प्रति लीटर निर्धारित था। इससे मिलों के लिए एथेनॉल एक महत्वपूर्ण

वैकल्पिक राजस्व स्रोत बन गया। यहीं फूड बनाम फ्यूल का प्रश्न सटीकता से वास्तविक रूप लेता है।

साथियों, 21 अगस्त 2026 को यहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया राजनीतिक आरोप बहस को और तीखा बनाता है। उन्होंने केंद्र की ई-20 नीति को चीनी की कीमतों में तेजी से जोड़ते हुए दावा किया कि एथेनॉल के लिए गन्ने और चीनी की दिशा बदलने से बाजार में कमी पैदा हुई। उनके आरोप को राजनीतिक बयान के रूप में अलग रखा जा सकता है,लेकिन जिस मूल आर्थिक प्रश्न की ओर वे संकेत करते हैं,यानी वैकल्पिक उपयोग के कारण किसी वस्तु की घरेलू उपलब्धता पर दबाव उसे आंकड़ों के आधार पर जांचना आवश्यक है।

दूसरी ओर, सरकार की नीति का मूल उद्देश्य भी केवल पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना नहीं था; इसका एक उद्देश्य चीनी उद्योग में अतिरिक्त स्टॉक, मिलों की नकदी समस्या व किसानों के बकाए का समाधान करना भी रहा है। सरकार ने 2021 में स्पष्ट किया था कि एथेनॉल के लिए डायवर्ट की गई मात्रा को चीनी मिलों के मासिक रिलीज कोटा में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसलिए आज की महंगाई के लिए केवल ई-20 को विलेन घोषित करना आर्थिक रूप से उतना ही सरलीकरण होगाजितना उसे पूरी तरह निर्दोष मान लेना। वास्तविकता कई कारणों का संगम है। पहला बड़ा कारण उत्पादन में कमजोरी है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और उप्र जैसे प्रमुख गन्ना क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम ने उत्पादन और उपलब्धता पर दबाव डाला है। इसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2026 की शुरूआत में चीनी का शुरूआती स्टॉक लगभग 35 लाख टन तक गिरने का अनुमान लगाया गया है, जिसे करीब 3 दशकों का निम्न स्तर बताया गया है।

यूपीआई का स्वर्णिम दशक

@ प्रमोद तिवारी

एक समय था जब छोटी-सी खरीदारी के लिए भी जेब में नकद रखना जरूरी माना जाता था। सब्जी खरीदनी हो, चाय पीनी हो, किराने का सामान लेना हो या किसी दोस्त को पैसे भेजने हों, नकद या बैंक ट्रांसफर ही मुख्य विकल्प थे। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मोबाइल फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा। इस बदलाव के केंद्र में है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। अगस्त 2026 में भारत ने यूपीआई के सफल और ऐतिहासिक दस साल पूरे किए हैं। इन दस वर्षों में यूपीआई केवल भुगतान का एक माध्यम नहीं रहा, बल्कि इसने देश में पैसे के लेन-देन का तरीका ही बदल दिया। इसकी शुरूआत जिस दौर में हुई थी, उस समय डिजिटल भुगतान आज की तरह आम जिंदगी का हिस्सा नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे यूपीआई ने बैंक, मोबाइल फोन, दुकानदार और ग्राहक को एक ही डिजिटल व्यवस्था में जोड़ दिया। दस साल की इस यात्रा की सबसे बड़ी तस्वीर आंकड़ों में दिखाई देती है। यूपीआई के जरिए होने वाले लेन-देन की कुल वैल्यू ₹0.07 ट्रिलियन से बढ़कर ₹314 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। यह वृद्धि केवल संख्या बढ़ने की कहानी नहीं है। यह बताती है कि भारत के लोगों ने डिजिटल भुगतान को कितनी तेजी से अपनाया है। आज सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर बड़े स्टोर तक, छोटे दुकानदार से लेकर ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों तक, यूपीआई का इस्तेमाल दिखाई देता है। शहरों के साथ-साथ छोटे कस्बों और गांवों में भी क्यूआर कोड आम दृश्य बन चुका है।

यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने विकसित किया। एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई एक तत्काल भुगतान प्रणाली है, जो अलग-अलग बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे भेजने की सुविधा देती है। यह व्यवस्था आईएमपीएस के बुनियादी ढांचे पर विकसित की गई है।

यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता रही। ग्राहक को बैंक खाते की लंबी जानकारी हर बार देने की जरूरत नहीं पड़ी। मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए भुगतान करना आसान हुआ। इसने भुगतान को बैंक की शाखा और एटीएम की सीमाओं से बाहर निकालकर मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया। शुरूआती दौर में यूपीआई को अपनाने की गति बहुत तेज नहीं थी। लोगों को नई व्यवस्था पर भरोसा बनाने में समय लगा। लेकिन जैसे-जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा, यूपीआई भी तेजी से आगे बढ़ा। फिर आया वह दौर जब डिजिटल भुगतान रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया।

छोटी रकम से लेकर बड़े भुगतान तक

यूपीआई की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसने भुगतान की राशि को महत्वपूर्ण नहीं रहने

दिया। कुछ रुपये का भुगतान हो या हजारों रुपये का–प्रक्रिया लगभग उतनी ही आसान रही। यही कारण है कि यूपीआई का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के बीच तेजी से बढ़ा। एक कप चाय के पैसे देने से लेकर घर का सामान खरीदने तक, हर जगह डिजिटल भुगतान दिखाई देने लगा। कई दुकानदारों के लिए क्यूआर कोड रखना उतना ही सामान्य हो गया जितना दुकान में तराजू या कैश बॉक्स रखना। इस बदलाव का असर छोटे कारोबार पर भी पड़ा। दुकानदार को हर समय छुट्टे पैसे रखने की जरूरत कम हुई। ग्राहक के पास नकद नहीं होने पर भी खरीदारी संभव हुई। भुगतान का रिकॉर्ड मोबाइल में रहने लगा। इस तरह यूपीआई ने केवल भुगतान की गति नहीं बढ़ाई, बल्कि लेन-देन को अधिक व्यवस्थित भी बनाया।

आंकड़ों में यूपीआई

दस साल की यात्रा के दौरान यूपीआई का विस्तार जिस गति से हुआ, वह भारत के डिजिटल बदलाव की बड़ी तस्वीर पेश करता है। ठढउक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में यूपीआई पर 22,716.07 मिलियन लेन-देन दर्ज किए गए। इन लेन-देन का कुल मूल्य ₹28,92,138.67 करोड़ रहा। इसी महीने 731 बैंक यूपीआई पर लाइव थे। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपीआई अब कोई सीमित डिजिटल सेवा नहीं है। यह देश के भुगतान ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज लोग बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, खरीदारी, टिकट, फीस और कई दूसरी सेवाओं का भुगतान डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। कई जगह भुगतान के लिए सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करना पर्याप्त होता है। यूपीआई ने पैसे भेजने और लेने के बीच का अंतर भी कम किया है। भुगतान अब इंतजार का काम नहीं रहा। एक खाते से दूसरे खाते में रकम कुछ ही क्षणों में पहुंच सकती है।

डिजिटल इंडिया को मिली नई गति

यूपीआई की सफलता को भारत के व्यापक डिजिटल बदलाव से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सस्ता और तेज इंटरनेट, स्मार्टफोन का बढ़ता इस्तेमाल, बैंक खातों का विस्तार और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता ने यूपीआई के लिए मजबूत आधार तैयार किया। लेकिन केवल तकनीक उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं था। लोगों को ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो आसान हो और अलग-अलग बैंकों तथा ऐप के बीच काम करे। यूपीआई ने इसी जरूरत को पूरा किया। एनपीसीआई का उद्देश्य भारत में एक मजबूत और व्यापक भुगतान ढांचा तैयार करना रहा है। संगठन के अनुसार उसका फोकस नई तकनीक के माध्यम से खुदरा भुगतान प्रणाली में नवाचार और उसकी पहुंच बढ़ाने पर है। यूपीआई इसी सोच का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया।

गांव और छोटे कारोबार तक पहुंच

डिजिटल भुगतान की चर्चा अक्सर बड़े शहरों और आधुनिक बाजारों के संदर्भ में होती है। लेकिन यूपीआई की असली ताकत उसकी व्यापक पहुंच में दिखाई देती है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में भी क्यूआर कोड आधारित भुगतान तेजी से सामान्य हुआ है। ऐसे दुकानदार जो कभी केवल नकद भुगतान लेते थे, अब डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। इससे ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए सुविधा बढ़ी है। डिजिटल भुगतान ने छोटे कारोबारियों के लिए लेन-देन का रिकॉर्ड रखने की संभावना भी बढ़ाई है। कारोबार के डिजिटल होने से भविष्य में औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ने के साथ डिजिटल समझ और सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ी है। हर उपयोगकर्ता के लिए यह समझना जरूरी है कि भुगतान करते समय किस जानकारी को साझा करना है और किसे नहीं।

बैंकिंग को भी मिला नया रास्ता

यूपीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी भुगतान व्यवस्था को नया रूप दिया। आज

एक ग्राहक अलग-अलग बैंक खातों को डिजिटल भुगतान ऐप के माध्यम से इस्तेमाल कर सकता है। यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी ने अलग-अलग बैंक और भुगतान सेवाओं के बीच जुड़ाव को आसान बनाया। एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई पर सैकड़ों बैंक और भुगतान संस्थान जुड़े हुए हैं। यह नेटवर्क जितना बड़ा हुआ, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा उतनी ही बढ़ती गई। यूपीआई का इस्तेमाल केवल दुकानों में भुगतान तक सीमित नहीं रहा। इसका उपयोग आईपीओ के आवेदन में भी किया जा सकता है। एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई के जरिए आईपीओ आवेदन में निवेशक के खाते में राशि ब्लॉक की जा सकती है और आवंटन के अनुसार राशि का इस्तेमाल किया जाता है। इससे साफ है कि यूपीआई अब केवल रोजमर्रा की खरीदारी का माध्यम नहीं है। यह वित्तीय सेवाओं के बड़े हिस्से से जुड़ता जा रहा है।

भाषा और तकनीक की नई दिशा

डिजिटल भुगतान को वास्तव में आम बनाने के लिए केवल तकनीक काफी नहीं है। भाषा भी महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग अलग-अलग भारतीय भाषाएं बोलते हैं, वहां डिजिटल सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में ठढउकने आवाज आधारित भुगतान की सुविधा पर भी काम किया है। 'हेलो! यूपीआई' जैसी पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में आवाज के माध्यम से डिजिटल भुगतान को आसान बनाना है। एनपीसीआई के अनुसार यह सुविधा स्मार्ट फोन के साथ-साथ कुछ अन्य उपकरणों और दूरसंचार माध्यमों के जरिए भी भुगतान अनुभव को सरल बनाने की दिशा में काम करती है। इस तरह यूपीआई का अगला चरण केवल तेज भुगतान नहीं, बल्कि ज्यादा लोगों तक आसान भुगतान पहुंचाना भी है।

विदेशों तक पहुंचता भारतीय मॉडल

यूपीआई की कहानी अब केवल भारत की कहानी नहीं रह गई है। भारत ने डिजिटल भुगतान के इस मॉडल को दूसरे देशों के साथ भी साझा किया है। यूपीआई की स्वीकार्यता और विभिन्न देशों में इसके विस्तार ने भारत की डिजिटल भुगतान क्षमता को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। एनपीसीआई ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी कुछ परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के जरिए यूपीआई उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराई है, बशर्ते संबंधित बैंक व सेवा इसकी अनुमति देते हों। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि यूपीआई भारतीय जरूरत से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था का हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी

यूपीआई की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है–डिजिटल सुरक्षा। जब भुगतान मोबाइल फोन से होने लगे तो उपयोगकर्ता को अपने बैंक खाते, यूपीआई पिन और अन्य जानकारी को सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। एनपीसीआई स्पष्ट रूप से सलाह देता है कि यूपीआई पिन किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। भुगतान अधिकृत करने के लिए पिन का इस्तेमाल होता है और इसे गोपनीय रखना जरूरी है। डिजिटल भुगतान के विस्तार के साथ लोगों को यह भी समझना होगा कि किसी भुगतान को प्राप्त करने के लिए हर बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती। किसी अनजान व्यक्ति के भेजे अनुरोध को स्वीकार करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है। यूपीआई की सफलता तभी स्थायी होगी जब सुविधा के साथ सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए।

स्वर्णिम दशक से अगले दशक की ओर

अगस्त 2026 में यूपीआई के दस साल पूरे होना भारत की डिजिटल यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ₹0.07 ट्रिलियन से ₹314 ट्रिलियन तक पहुंची लेन-देन की वैल्यू इस बदलाव की गति को दिखाती है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दस वर्षों में यूपीआई के सामने और बड़ी संभावनाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आवाज आधारित तकनीक, बेहतर सुरक्षा, स्थानीय भाषाओं और अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता के साथ डिजिटल भुगतान का दायरा और बढ़ सकता है। भारत ने पिछले दस वर्षों में यह साबित किया है कि जब तकनीक को सरल बनाया जाए और उसे आम लोगों की जरूरत से जोड़ा जाए, तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। यूपीआई इसी बदलाव का सबसे मजबूत उदाहरण है। दस साल पहले यह एक नई भुगतान व्यवस्था थी। आज यह करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की आदत बन चुकी है।

BIKANO is our range of Packaged Namkeens, Sweets, Sherbets, Papad and Pickles with a dependable shelf life. These are popular not only in India but also in the quality conscious overseas markets like Europe, America, Canada, Middle East and many more

VISIT BIKANERVALA OUTLETS IN : INDIA | USA | CANADA | U.A.E. | QATAR | BAHRAIN | UNITED KINGDOM | NEW ZEALAND | SINGAPORE | NEPAL

FOR BULK ORDER / BOOKINGS CALL ✆ 9528 214 214, 9971 877 211

Corporate Address: **BIKANERVALA PVT. LTD.** A-27, Lawrence Road Industrial Area, New Delhi - 110035

जलप्रलय की भयावह तस्वीर

त्रासदी की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 28 अगस्त तक नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या 550 से अधिक बताई गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। मौत और लापता लोगों का बढ़ता आंकड़ा इस त्रासदी की भयावहकता के प्रमाण है। नेपाल में अकेले करीब 93 हजार लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत बताई गई है।

@ गोपेन्द्र नाथ भट्ट

नेपाल इस समय आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक त्रासदियों में से एक से जूझ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल-चीन सीमा के निकट ग्लेशियस (हिमनद) के टूटने और भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान तथा मलबा नदियों में आने से अचानक आई अप्रत्याशित बाढ़ ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी घाटियों में विध्वंसक और व्यापक तबाही मचा दी। देखते ही देखते बस्तियां, सड़कें, पुल और महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग जल और मलबे की चपेट में आ गए।

त्रासदी की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 28 अगस्त तक नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या 550 से अधिक बताई गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। मौत और लापता लोगों का बढ़ता आंकड़ा इस त्रासदी की भयावहकता के प्रमाण है। नेपाल में अकेले करीब 93 हजार लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत बताई गई है। हजारों लोग विस्थापित होकर अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचना है, जिनके गांव और संपर्क मार्ग मलबे में तब्दील हो चुके हैं। नेपाल की सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के हजारों जवान बचाव अभियान में जुटे हैं। हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाकों की निगरानी की जा रही है। अनेक लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पतालों और राहत शिविरों तक पहुंचाया गया है। भारत सरकार की ओर से भी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस त्रासदी को केवल एक बार आई बाढ़ मानना गंभीर भूल होगी। क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ग्लेशियस के टूटने के बाद बने मलबे और पानी के अवरोध से नए जलाशय बनने तथा उनके अचानक टूटने का खतरा अभी भी बना हुआ है। पड़ौसी देश चीन की ओर से भी ऐसी चेतावनियाँ दी जा रही है यही कारण है कि बचाव अभियान के साथ-साथ नदियों के जलस्तर और संभावित नए जलप्रवाह पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। राहतकर्मियों के सामने एक ओर मलबे में दबे लोगों को खोजने की चुनौती है, तो दूसरी ओर नए भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी मौजूद है।

आपदा ने नेपाल के परिवहन और आर्थिक ढांचे को भी गहरा झटका दिया है। क्योंकि नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आधारभूत ढांचा तहस नहस और ढह गया है। कई सड़कें और पुल बह गए हैं। हाइड्रो पावर स्टेशन तबाह हो गए है। चीन के साथ व्यापार और आवागमन का महत्वपूर्ण सीमा संपर्क भी प्रभावित हुआ है। जल विद्युत परियोजनाओं और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचने से पुनर्निर्माण की चुनौती और बढ़ गई है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध पूरा हिमालयी क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है। नेपाल की वर्तमान त्रासदी हिमालयी क्षेत्र में तेजी से बदलते पर्यावरण की एक गंभीर चेतावनी भी है। जलवायु परिवर्तन की चेतावनी के चलते बढ़ते तापमान से ग्लेशियरों और ग्लेशियस झीलों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी हिमनद झील के अचानक फटने की घटनाएं भविष्य में अधिक गंभीर खतरा बन सकती हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में केवल राहत और पुनर्वास पर्याप्त नहीं होंगे।

हिमालयी क्षेत्र में साझा निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, वैज्ञानिक अध्ययन व सीमा पार आपदा प्रबंधन को व अधिक मजबूत करना होगा ताकि ऐसी दुखदायी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के पुख्ता उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। नेपाल की इस त्रासदी में पड़ोसी भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी सहायता के लिए आगे आया है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता मलबे में जिंदगी तलाशना, विस्थापितों को भोजन-पानी व चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा संभावित दूसरी आपदा से लोगों को बचाना है। नेपाल की यह त्रासदी केवल एक देश की विपदा नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए प्रकृति की गंभीर चेतावनी है। विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन अब विकल्प नहीं, एक अनिवार्यता बन चुका है।

भारत की सदाशयता

नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित भोटेकोशी और त्रिशूली नदी घाटियों में एक अभूतपूर्व और प्रलयकारी प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है। यह अचानक आई भयानक बाढ़ हिमालयी क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों का साक्षात प्रमाण है। प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार, पहाड़ों के उच्च शिखर पर एक विशाल ग्लेशियर के टूटने और उसके कारण हुए तीव्र भूस्खलन ने भोटेकोशी नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। यह भूस्खलन इतना शक्तिशाली था कि भूकंपीय तरंगों ने इसे स्थानीय स्तर पर रिक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता के रूप में दर्ज किया।

इस महासंकट के सामने आते ही भारत ने पलक झपकते ही अपनी 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' की भूमिका को धरातल पर उतारा। आपदा के कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से सीधी बात की और भारत की ओर से बिना शर्त पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कूटनीतिक औपचारिकताओं से परे हटकर भारतीय वायुसेना ने तुरंत अपने विशेष सी-130जे सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमान को काठमांडू के लिए रवाना किया, जो 10 टन से अधिक आपातकालीन मानवीय सहायता व चिकित्सा

सामग्री की पहली खेप लेकर पहुंचा। इस राहत सामग्री में प्रभावित परिवारों के लिए तिरपाल, वाटरप्रूफ टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, जल शोधन के लिए क्लोरीन की गोलियां और भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं शामिल थे। इसके समानांतर, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के गृह मंत्रालय और नेपाली सेना के साथ मिलकर एक 247 विशेष समन्वय केंद्र और हेल्पलाइन की शुरूआत की है। दुर्गम पहाड़ी घाटियों में फंसे भारतीय नागरिकों, तीर्थयात्रियों और नेपाली भाइयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय खोजी टीमों और नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे के कारण संचार और बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाने के कारण, भारत ने नेपाल को सैटेलाइट फोन और तकनीकी सहायता भी प्रदान की है ताकि दुर्गम इलाकों से संपर्क बहाल हो सके।

अगस्त 2026 की यह बाढ़ पहली घटना नहीं है जब भारत ने नेपाल की ढाल बनकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई हो। वर्ष 2015 का नेपाल भूकंप इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जब भीषण भूकंप ने नेपाल के बुनियादी ढांचे को तोड़ दिया था। तब भारत ने कुछ ही घंटों के भीतर 'ऑपरेशन मैत्री' शुरू किया था, जो किसी भी विदेशी भूमि पर भारत का सबसे बड़ा नागरिक राहत अभियान था। भारतीय जवानों ने मलबे से जिंदगियां निकाली थीं और भारत ने नेपाल के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए एक अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी थी। इसी तरह, कोविड-19 महामारी के दौरान जब दुनिया स्वार्थी 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' से घिरी थी, तब भारत ने 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत कोविशील्ड टीकों की लाखों खुराकें मुफ्त अनुदान के रूप में नेपाल भेजी थीं। नेपाल में ऑक्सीजन का संकट गहराने पर भारत ने घरेलू किल्लत के बावजूद सीमाओं को खुला रखा और टैंकरों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की थी।

नेपाल के प्रति भारत की नीतियां और हालिया बाढ़ आपदा में उसकी त्वरित प्रतिक्रिया यह साबित करती है कि भारत केवल एक बड़ा पड़ोसी देश नहीं, बल्कि सुख-दुख का एक विश्वसनीय साथी है। भू-राजनीतिक समीकरणों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, और बाहरी ताकतें (जैसे चीन का ऋण-जाल आधारित बीआरआई निवेश) नेपाल को लुभाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन भारत का मानवीय और निस्वार्थ सहयोग किसी रणनीतिक सौदेबाजी पर निर्भर नहीं है। अगस्त 2026 की इस त्रासदी ने पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक फैले सांस्कृतिक ताने-बाने और दोनों देशों के बीच की खुली सीमा की प्रासंगिकता को व गहरा कर दिया है। वैश्विक पटल पर जब भी पड़ोसियों के प्रति उदारता, सह-अस्तित्व और जिम्मेदारी की बात होगी, संकट की इस घड़ी में नेपाल की ढाल बनकर खड़ा रहने का भारत का यह संकल्प हमेशा एक बेमिसाल अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।

नेपाल से भारत को सबक लेने की जरूरत

नेपाल की घटना भारत के लिए भी गहरी चेतावनी है। इस चेतावनी से सीख लेने की जरूरत है। उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की ऋषिगंगा आपदा और हिमालयी राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़, भूस्खलन एवं बादल फटने की घटनाएं पहले ही बता चुकी हैं कि पहाड़ों की सहनशीलता असीमित नहीं है। हिमालय में सड़कें, सुरंगें, जलविद्युत परियोजनाएं, होटल, बस्तियां और अन्य निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के नाम पर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके लिए पर्वतीय पर्यावरण की वहन क्षमता का पर्याप्त आकलन हो रहा है? विकास जरूरी है, मगर ऐसा विकास जो पहाड़ों को खोखला करके ही संभव हो, अंततः मानव जीवन और स्वयं विकास दोनों के लिए संकट बन सकता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता 'आपदा के बाद राहत' से आगे बढ़कर 'आपदा से पहले तैयारी' की है।

संस्कृति समाज राष्ट्र निर्माण

राष्ट्र समाज

आपकी आवाज...

जन से जन तक
राष्ट्र की आवाज

"काशी की बेटी
रानी लक्ष्मीबाई
हमारी प्रेरणा,
हमारी शक्ति"

"वीरता
नारी की पहचान है,
और राष्ट्र उसकी शक्ति"

प्रायोजन आमंत्रण पत्र
SPONSORSHIP INVITATION LETTER

दिनांक: ____________

विषय: काशी की बेटी रानी लक्ष्मीबाई जयंती एवं राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2026 हेतु प्रायोजन आमंत्रण

महोदय/महोदया,

राष्ट्रसमाज द्वारा **19 नवंबर 2026** को Constitution Club of India, New Delhi में **"काशी की बेटी रानी लक्ष्मीबाई जयंती एवं राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2026"** का आयोजन किया जा रहा है।

इस आयोजन के माध्यम से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य एवं राष्ट्रभक्ति को सम्मानित करने के साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हम आपके प्रतिष्ठित संस्थान को **मुख्य प्रायोजक / प्रायोजक / सहयोगी प्रायोजक** के रूप में हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आपका सहयोग इस विशेष आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। Sponsorship के अनुसार आपके संस्थान को कार्यक्रम की प्रचार एवं Branding में उचित स्थान प्रदान किया जाएगा।

हम आपके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

साझेदारी
एक बेहतर समाज के लिए

सम्मानता
सशक्त समाज के लिए

सहयोग
उज्ज्वल भविष्य के लिए

सादर,

डॉ. प्रमोद तिवारी
राष्ट्र समाज

इतिहास से प्रेरणा
भविष्य के लिए संकल्प

19 नवंबर 2026
गुरूवार

Constitution Club of India
New Delhi

पता: 298/299 B-9, Sector 5
Rohani, New Delhi 110086

Mob: 83682767, 9911662767
rashtrasamaj@gmail.com rashtak.com

एक सशक्त समाज
एक समृद्ध भारत

नितिन नवीन की नई टीम नई ऊर्जा और नया संतुलन

@ ललित गर्ग

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के साथ यह संकेत दे दिया है कि भाजपा अब संगठन को केवल पदों के पुनर्विन्यास के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप नए सिरे से गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 17 अगस्त 2026 को घोषित नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिवों सहित संगठन के विभिन्न स्तरों पर व्यापक परिवर्तन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई टीम को संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव का मिश्रण बताया है। इस टीम को समझने के लिए इसे केवल 'कौन आया और कौन गया' के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे भाजपा की दीर्घकालीन संगठनात्मक रणनीति, सामाजिक समीकरणों की समझ और आने वाले चुनावों की राजनीतिक चुनौतियों को पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन की टीम का सबसे बड़ा संदेश है- अनुभव को हटाकर युवा ऊर्जा नहीं लाई गई है, बल्कि अनुभव के साथ नई ऊर्जा को जोड़ा गया है। यही संतुलन किसी बड़े राजनीतिक संगठन को गतिशील बनाता है।

राम माधव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में वापसी इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन, वैचारिक संवाद और रणनीतिक राजनीति की उनकी समझ भाजपा के लिए उपयोगी हो सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डी. पुरंदेश्वरी, बैजयंत पांडा, तीरथ सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर यह स्पष्ट किया गया है कि नितिन नवीन ने वरिष्ठता और अनुभव को किनारे नहीं किया है। यह उस संगठनात्मक सोच का प्रमाण है जिसमें पुराने अनुभव को नई परिस्थितियों के अनुरूप इस्तेमाल करने की कोशिश दिखाई देती है। दूसरी ओर स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी देना भी केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं है। स्मृति ईरानी का राजनीतिक व्यक्तित्व आक्रामक संवाद, महिला मतदाताओं से जुड़ाव और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी राजनीतिक संप्रेषण से जुड़ा रहा है। उनकी वापसी भाजपा के लिए राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक उपयोगिता-दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उनके साथ विनोद तावड़े, सुनील बंसल जैसे संगठनात्मक अनुभव रखने वाले नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी मिलना संगठन और चुनावी प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल की ओर संकेत करता है।

पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया जाना भी उल्लेखनीय है। यह जिम्मेदारी बताती है कि संगठन में राजनीतिक अनुभव के साथ प्रशासनिक, आर्थिक और पेशेवर दक्षता को भी महत्व दिया जा रहा है। बी. एल. संतोष का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहना संगठन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। अर्थात नितिन नवीन ने पूरी तरह से 'पुराना हटाओ, नया लाओ' की नीति नहीं अपनाई, बल्कि जहां निरंतरता आवश्यक थी वहां उसे बनाए रखते हुए परिवर्तन के लिए

पर्याप्त जगह बनाई है। नई टीम का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है। भाजपा के लिए अब राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, समाज के अलग-अलग वर्गों में संगठन की स्वीकार्यता और पहुंच बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नई टीम में महिलाओं, विभिन्न सामाजिक समुदायों, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक के प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार टीम में महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को भी उल्लेखनीय जगह मिली है।

यहां एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है-भाजपा अब केवल अपने परंपरागत समर्थक वर्ग से संवाद करने के बजाय नए मतदाता समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। युवा, प्रथम बार मतदान करने वाली पीढ़ी, शहरी पेशेवर, तकनीक से जुड़े वर्ग और महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाएं आज चुनावी परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसलिए संगठन में ऐसे चेहरों की आवश्यकता है जो केवल राजनीतिक भाषण न दें, बल्कि बदलते समाज की भाषा समझें। भाजपा की नई टीम में इस दिशा का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है। विशेष रूप से युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के स्तर पर किए गए बदलाव इस बात का संकेत हैं कि संगठन भविष्य के मतदाता को आज से ही संबोधित करना चाहता है। जेन-जी को केवल सोशल मीडिया की पीढ़ी मानना भूल होगी। यह पीढ़ी रोजगार, तकनीक, उद्यमिता, पारदर्शिता, राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अवसरों को लेकर अलग तरह की अपेक्षाएं रखती है। भाजपा यदि इस पीढ़ी से वास्तविक संवाद स्थापित कर पाती है तो उसका लाभ केवल आगामी चुनाव में नहीं, बल्कि 2030 और 2040 के दशक की राजनीति में भी मिल सकता है।

नई टीम का सबसे बड़ा राजनीतिक परीक्षण हालांकि उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में होगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन की

मजबूती का सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। आगामी चुनावों की दृष्टि से भाजपा के सामने केवल सत्ता विरोधी भावनाओं का मुकाबला करने की चुनौती नहीं है, बल्कि विपक्ष के बदलते गठजोड़, जातीय समीकरण, युवाओं की आकांक्षाओं और स्थानीय मुद्दों को भी साधना है। इसलिए राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चुनावी दृष्टि से स्वाभाविक रणनीति है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नई टीम का उद्देश्य केवल 2026-27 के चुनाव नहीं हो सकते। भाजपा की दृष्टि निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे आगे तक जाती है। 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य तभी राजनीतिक व सामाजिक आधार प्राप्त कर सकता है जब पार्टी संगठन निरंतर नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ता रहे। इसलिए नितिन नवीन की टीम को एक प्रकार से 2029 की तैयारी 2047 की राजनीतिक-संगठनात्मक नींव के रूप में भी देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के स्तर पर भी आने वाले समय में परिवर्तन या विस्तार की अटकलें स्वाभाविक हैं, विशेषकर जब सरकार को आगामी राज्यों के राजनीतिक समीकरणों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को साथ लेकर चलना है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में अभी किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति को निश्चित मानना उचित नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जैसे अनुभवी नेताओं के संभावित भविष्य की चर्चा राजनीतिक हलकों में हो सकती है, पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व पर निर्भर करेगा। नरेन्द्र मोदी की राजनीति में संगठन और सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों के माध्यम से ऊर्जा पैदा करने की परंपरा रही है, इसलिए भविष्य में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो तो उसे आश्चर्य के बजाय व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाना चाहिए। वास्तव में नितिन नवीन की नई टीम का सबसे बड़ा संदेश 'रीसेट' नहीं, 'रीकैलिब्रेशन' है-अर्थात संगठन को पूरी तरह बदलना नहीं, बदलते राजनीतिक वातावरण के अनुरूप उसकी दिशा और गति को पुनर्संतुलित करना। वरिष्ठ नेताओं का अनुभव, युवाओं की ऊर्जा, महिलाओं की बढ़ती भूमिका, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक विविधता और पेशेवर दक्षता-इन सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास दिखाई देता है। नई टीम में 65 पदाधिकारियों में बड़ी संख्या में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की बात भी सामने आई है, जो संगठन में पीढ़ीगत बदलाव की गति को दर्शाती है।

अब असली चुनौती पद प्राप्त करने वालों की नहीं, परिणाम देने वालों की होगी। संगठन कितना जमीनी बनेगा, कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच संवाद कितना मजबूत होगा, सोशल मीडिया के शोर के बाहर जनता की वास्तविक समस्याओं को कितना समझा जाएगा और युवाओं-महिलाओं सहित नए सामाजिक वर्गों का विश्वास कितना अर्जित किया जाएगा-इन्हीं कसौटियों पर नितिन नवीन की नई टीम का मूल्यांकन होगा। कुल मिलाकर यह टीम भाजपा की उस राजनीति की तस्वीर प्रस्तुत करती है जिसमें अनुभव को विरासत, युवा ऊर्जा को भविष्य और सामाजिक विविधता को विस्तार का माध्यम बनाया गया है। यदि नितिन नवीन इस टीम की क्षमताओं को एक साझा संगठनात्मक लक्ष्य में बदल पाए, तो यह परिवर्तन केवल भाजपा के पदाधिकारियों की सूची में बदलाव नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी की कार्यशैली, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति में दिखाई देने वाला परिवर्तन बन सकता है।

डोभाल की कूटनीति और भारत-चीन संबंधों की नई करवट

@ राष्ट्र समाज

भारत और चीन के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों की तल्खी के बाद अब संवाद, संयम और व्यावहारिक सहयोग का एक नया दौर दिखाई दे रहा है। इसे किसी अचानक आए परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को साथ लेकर चलने वाली एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। इस बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर सामने आई है। 25 अगस्त को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता ने इस प्रक्रिया को ठोस आधार दिया है। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, सीमा निर्धारण की दिशा में शीघ्र एवं सार्थक प्रगति करने तथा सैन्य-द्विपक्षीय संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने पर सहमति बनाई है। डोभाल की बीजिंग यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह केवल सीमा विवाद पर बातचीत नहीं थी। यह उस व्यापक प्रश्न पर विमर्श था कि क्या भारत और चीन प्रतिस्पर्धा के बावजूद सह-अस्तित्व, स्थिरता और पारस्परिक हितों का रास्ता तलाश सकते हैं। दोनों देशों ने दो अतिरिक्त सैन्य संपर्क-बिंदु और पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में दो अतिरिक्त सैन्य दूरभाष संपर्क स्थापित करने पर सहमति जताई है। सीमा व्यापार, कैलाश-मानसरोवर यात्रा और सीमा-पार सहयोग को भी आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ है।

अजीत डोभाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सुरक्षा और कूटनीति को परस्पर विरोधी नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है- मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था ही प्रभावी कूटनीति की आधारभूमि बन सकती है। चीन के संदर्भ में भी भारत का संदेश यही रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना द्विपक्षीय संबंधों का पूर्ण सामान्यीकरण संभव नहीं है। 25वें दौर की

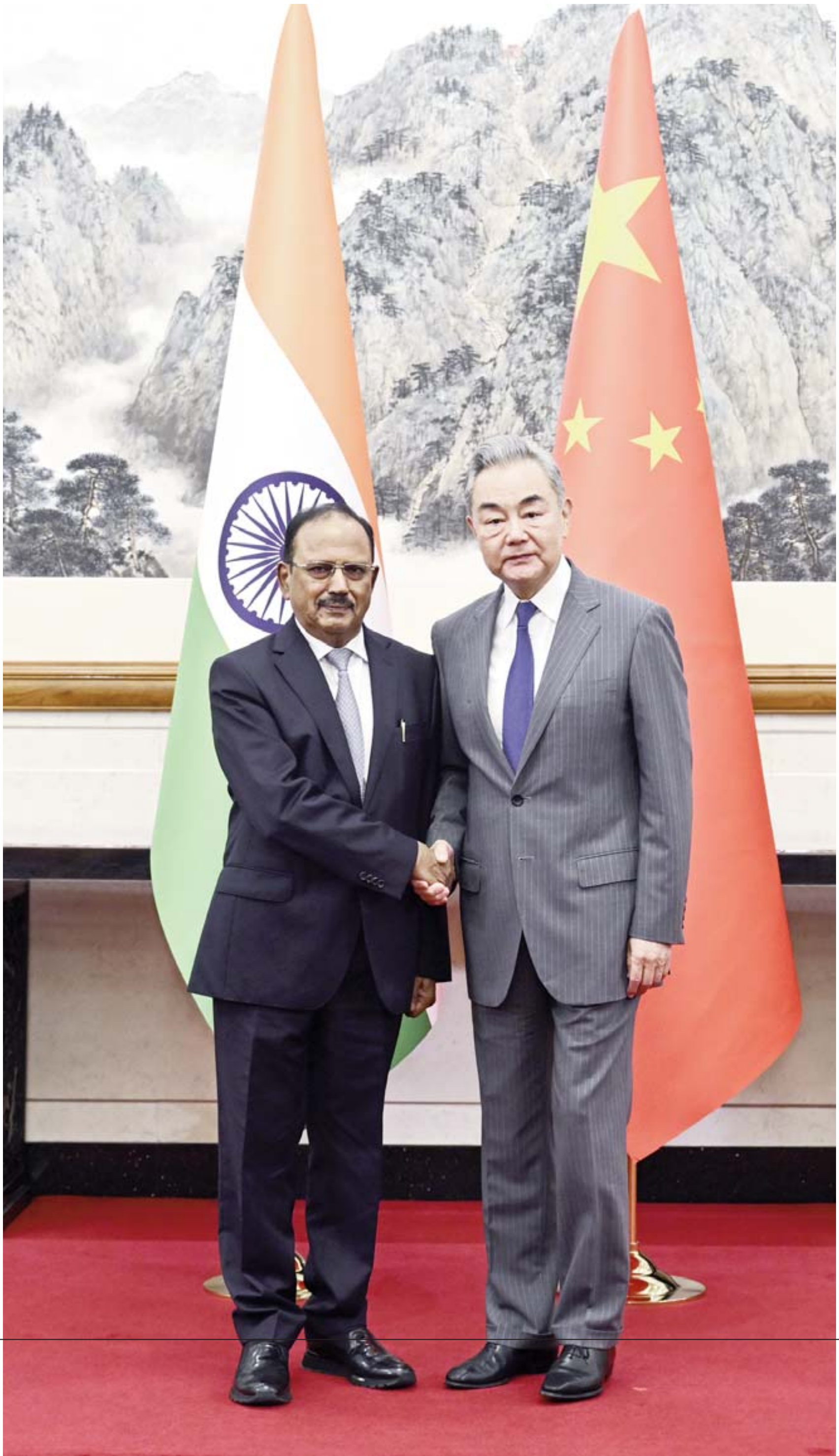

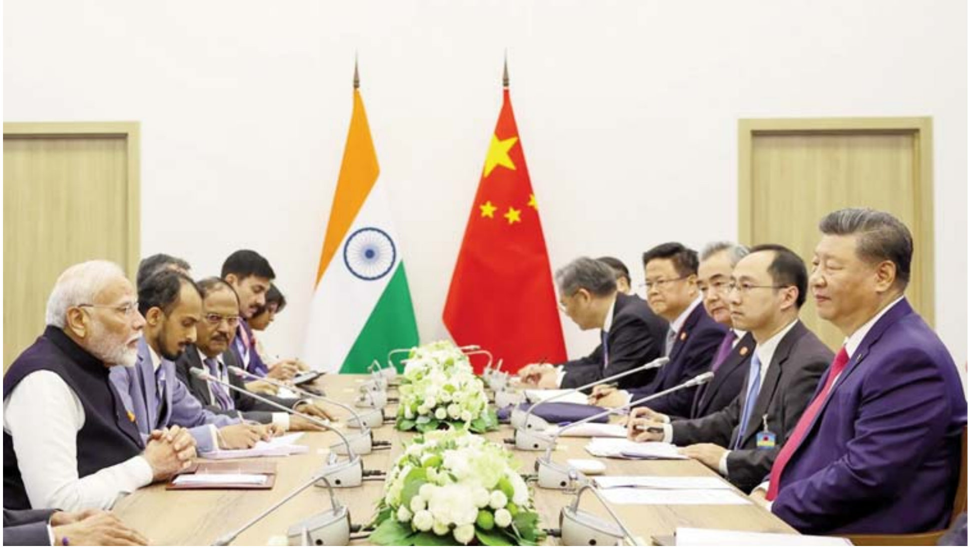

वार्ता में यही भारतीय दृष्टिकोण प्रमुखता से सामने आया। डोभाल का व्यक्तित्व केवल वार्ताकार का नहीं, बल्कि सुरक्षा रणनीतिकार का है। वे लंबे समय तक खुफिया तंत्र में रहे, विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में काम किया और बाद में खुफिया ब्यूरो के प्रमुख बने। भारत सरकार के अनुसार, उन्होंने पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी कार्यशैली में एक उल्लेखनीय संतुलन दिखाई देता है-जहां आवश्यक हो वहां कठोरता और जहां अवसर हो वहां संवाद। उड़ी के बाद की सर्जिकल कार्रवाई, बालाकोट की कार्रवाई, डोकलाम संकट के दौरान कूटनीतिक प्रयास और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका इसी व्यापक दृष्टिकोण के उदाहरण माने जाते हैं। 2026 में उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया।

भारत-चीन संबंधों का सबसे कठिन दौर वर्ष 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद आया। चार वर्षों तक सीमा पर सैन्य तनाव बना रहा। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच सैनिकों की पूर्ण वापसी और संबंधित विवादों के समाधान के बाद संबंधों को धीरे-धीरे पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी वर्ष कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति तथा मतभेदों को संबंधों की समग्र दिशा को प्रभावित न करने देने पर जोर दिया था। यही वह बिंदु था जहां डोभाल की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। दिसंबर 2024 में विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत से शुरू हुई प्रक्रिया अब 25वें दौर तक पहुंची है। इस बार आठ बिंदुओं पर बनी सहमति संकेत देती है कि बातचीत केवल औपचारिकता नहीं रह गई है। सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ तथा कार्य समूहों को सक्रिय करना, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलतफहमी रोकने के लिए मौजूदा सैन्य एवं कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग और नए संपर्क तंत्र बनाना व्यावहारिक विश्वास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत-चीन संबंध केवल सैनिक चौकियों और राजनयिक बैठकों तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संपर्क भी रहा है। कैलाश-मानसरोवर यात्रा की पुनर्बहाली और विस्तार, सीमा व्यापार मार्गों को फिर खोलना तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। 2026 में कैलाश-मानसरोवर यात्रा लिपुलेख और नाथू ला, दोनों मार्गों से संचालित हुई है। 25वें दौर की वार्ता में तीन निर्धारित सीमा व्यापार केंद्रों को फिर खोलने की प्रगति का स्वागत किया गया तथा व्यापार और तीर्थयात्रा को और मजबूत करने पर सहमति बनी। यह छोटा कदम नहीं है। सीमा पर सैनिकों की संख्या घटाना एक सुरक्षा उपाय है, लेकिन सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के लिए व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाना दीर्घकालिक शांति की सामाजिक नींव तैयार करता है।

शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा एक अवसर भी है, परीक्षा भी है। इसी पृष्ठभूमि में 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की संभावना जताई जा रही है। यदि यह यात्रा होती है तो यह सात वर्षों में उनकी पहली भारत यात्रा होगी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उनके साथ लगभग चार सौ अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है। हालांकि 27 अगस्त तक चीन की ओर से उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए शी की संभावित यात्रा को केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी नहीं माना जाना चाहिए। यह भारत-चीन संबंधों की वास्तविक दिशा को परखने का अवसर हो सकती है। वर्ष 2019 का चेन्नई संवाद अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ था, लेकिन उसके एक वर्ष बाद गलवान ने संबंधों को गहरे संकट में डाल दिया। अब यदि शी नई दिल्ली आते हैं तो दोनों देशों के पास उस टूटे हुए विश्वास को सावधानी से जोड़ने का अवसर होगा। लेकिन भारत को उत्साह में अपनी मूल सुरक्षा चिंताओं को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे, सीमा निर्धारण का लंबित प्रश्न और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पारदर्शिता जैसी चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। इसलिए भारत की नीति मित्रता की आकांक्षा, राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं होनी चाहिए।

डोभाल की विशेषता यही है कि वे संवाद को कमजोरी नहीं बनने देते और शक्ति को टकराव का पर्याय भी नहीं बनाते। उनकी कूटनीति में संदेश स्पष्ट है-भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा कीमत पर नहीं, सहयोग चाहता है, लेकिन समानता के आधार परय संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन सीमा की वास्तविकताओं को भुलाकर नहीं। आज भारत-चीन संबंध जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां डोभाल की भूमिका संकटमोचक से आगे बढ़कर विश्वास-निमार्ता और सुरक्षा-आधारित कूटनीति के सूत्रधार की बनती दिखाई देती है। 25वें दौर की वार्ता में हुई आठ सूत्रीय सहमति इसका प्रमाण है कि कठिनतम मतभेदों के बीच भी संवाद के रास्ते खुले रखे जा सकते हैं। शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा इस प्रक्रिया को शीर्ष नेतृत्व की राजनीतिक दिशा दे सकती है। किंतु असली सफलता किसी एक शिखर बैठक की तस्वीर में नहीं, बल्कि सीमा पर स्थायी शांति, पारस्परिक विश्वास, व्यापारिक संपर्क और विवादों के न्यायसंगत समाधान में होगी। भारत को चीन से संबंध सुधारने हैं, लेकिन अपनी सामरिक स्वायत्तता और सुरक्षा-सजगता के साथ। डोभाल की कूटनीति का सार भी यही है-संवाद के दरवाजे खुले रहें, पर राष्ट्रीय हितों की चौखट कभी कमजोर न हो। यही दृष्टिकोण भारत-चीन संबंधों को टकराव से प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व और अंततः स्थायी शांति की ओर ले जाने की सबसे व्यावहारिक राह बन सकता है।

कुछ ही दिनों बाद राजस्थान के कोटा में भी 17 जून 2026 को राहुल गांधी के 'छात्र संवाद' कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' के आयोजन स्थल की अनुमति प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गयी थी। और कार्यक्रम के प्रचार के लिए लगाए गए कई होर्डिंग्स और पोस्टर्स को हटा दिया गया था।

राहुल गांधी : सत्ता के लिए गंभीर

@ तनवीर जाफरी

नेता विपक्ष राहुल गांधी की आवाज को दबाने व युवाओं तक उनकी पहुँच को नियंत्रित करने का सरकार का प्रयास पिछले दिनों एक बार फिर विफल हो गया जबकि प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला ग्राउंड में सांसद राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए 8 अगस्त को दे दी गयी। इसे प्रशासन की समझदारी ही कहा जायेगा कि उसने ग्राउंड के इस्तेमाल की पुनः अनुमति देकर छात्रों व युवाओं से होने वाले संभावित टकराव को टाल दिया। परन्तु मात्र दो दिनों के भीतर प्रशासन की इस पल्टीबाजी से यह सन्देश तो चला ही गया कि व्यवस्था द्वारा एक बार फिर राहुल गांधी को छात्रों व युवाओं से संवाद करने में विघ्न डालने की कोशिश की गयी। खबर यह भी है कि प्रयागराज के निकटवर्ती जिलों में अनेक छात्र छात्राओं को नजरबंद कर उन्हें सभा में पहुँचने से रोका गया। सभास्थल के आसपास सत्ता समर्थकों द्वारा राहुल गाँधी का विरोध करने वाले पोस्टर लगवाए गए। यहाँ तक कि भाजपा कार्यकताओं द्वारा आनंद भवन के पास राहुल गांधी के काफिले को काला झंडा एवं भगवा झंडा दिखाकर उनका विरोध किया गया। ऐसा लग रहा था कि किसी सत्ताधारी नेता का विरोध किया जा रहा हो। आयोजकों के अनुसार मौसम के चलते ग्राउंड में कीचड़ सफाई व सभास्थल को समतल बनाने में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई विशेष सहयोग नहीं किया गया। इन सब के बावजूद राहुल गांधी को सुनने के लिये भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा।

सवाल यह है कि क्या वजह है कि भाजपा द्वारा कई वर्षों तक करोड़ों रुपए खर्च कर राहुल गांधी की छवि को 'पप्पू' बनाने का नरेटिव गढ़ा गया और सोशल मीडिया पर उनकी छवि बिगाड़ने का बाकायदा अभियान चलाया गया ? भाजपा के आईटी सेल ने करोड़ों रुपये खर्च कर राहुल गांधी की राजनीतिक साख को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित अभियान चलाया। इस अभियान के तहत राहुल गांधी के भाषणों की अधूरी वीडियो क्लिप्स, मीम्स और भ्रामक प्रचार सामग्री के जरिये उन्हें एक अपरिपक्व राजनेता के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। उसी 'पप्पू' से आज भाजपा इतनी डरी हुई है कि जगह जगह उसे राहुल गांधी के कार्यक्रम निरस्त कराने, जनता से मिलने से उन्हें रोकने तथा उन्हें परेशान करने के लिये तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं? अभी गत 17 जुलाई को देहरादून में परेड ग्राउंड में भी इसी तरह का 'छात्रों की गूंज' आयोजित होना था जिसमें राहुल गांधी को छात्रों से रूबरू होना था। यहां भी प्रशासन ने पहले अनुमति दी फिर वहां पहले से एक अन्य सरकारी कार्यक्रम का बहाना बता कर परेड ग्राउंड की अनुमति रद्द कर दी। जबकि कांग्रेस का आरोप था कि उन्होंने 15 से 17 जुलाई तक के लिए परेड ग्राउंड की बाकायदा अग्रिम अनुमति ली थी और नगर निगम में 1.77 लाख की फीस भी जमा कराई थी। परन्तु शायद पुष्कर सिंह धामी सरकार राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और नीट पेपर लीक तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छात्रों के साथ होने वाले राहुल के इस सीधे संवाद से डर गई थी, जिसके कारण ऐन वक़्त पर झूठा बहाना बनाकर

चुनौती

अनुमति रद्द कर दी गई। इसके बाद कार्यक्रम का वेन्यू बदलकर देहरादून के ही बन्नू स्कूल मैदान में स्थानांतरित किया गया, जहां अंततः राहुल गांधी का यह छात्र संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ व अनुमान से भी अधिक युवा वहां पहुंचे।

इसी तरह उत्तराखंड के कोटद्वार में 4 जून 2026 को उत्तराखंड दौरे के दौरान कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) और अल्मोड़ा के कार्यक्रमों में प्रशासन ने राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की बात बताकर उतरने नहीं दिया था। इस के पीछे प्रशासन और पायलटों द्वारा खराब मौसम और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था। उस समय भी राहुल के कोटद्वार और अल्मोड़ा के सभी कार्यक्रम रद्द हो गए थे। उस समय भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रशासन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और यूकाडा पर सीधे सवाल उठाए थे। रावत ने आरोप लगाया था कि जब उसी हवाई मार्ग पर सरकार और अन्य निजी ऑपरेटरों की हेलीकॉप्टर सेवाएं सामान्य रूप से उड़ान भर रही थीं और अल्मोड़ा से हल्द्वानी के बीच आवाजाही हो रही थी, तो सिर्फ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को ही उड़ान भरने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने जानबूझकर 'खराब मौसम' का बहाना बनाया ताकि राहुल गांधी युवाओं, पूर्व सैनिकों और आम जनता से संवाद न कर सकें।

इसके कुछ ही दिनों बाद राजस्थान के कोटा में भी 17 जून 2026 को राहुल गांधी के 'छात्र संवाद' कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' के आयोजन स्थल की अनुमति प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गयी थी। और कार्यक्रम के प्रचार के लिए लगाए गए कई होर्डिंग्स और पोस्टर्स को हटा दिया गया था। उस समय सत्ताधारी भाजपा नेताओं ने यह तर्क दिया था कि 21 जून को होने वाली नीट पुनः परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले इस तरह की राजनैतिक रैली आयोजित करने से कोचिंग के छात्रों में मानसिक तनाव पैदा होगा। जबकि कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग हब के संस्थानों और हॉस्टल मालिकों को छात्रों के इस कार्यक्रम में न भेजने के लिए डराया-धमकाया था।

इससे पूर्व भी राहुल गाँधी पर जगह जगह मानहानि के मुकदमे दायर करवाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की गयी। प्रवर्तन निदेशालय ई डी द्वारा ने जून 2022 में वित्तीय लेनदेन में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राहुल गांधी से 5 दिनों में लगभग 50 से 55 घंटे तक तीखे सवाल-जवाब किए गए। हर दिन उन्हें सुबह बुलाकर देर रात तक करीब 10 से 12 घंटे रोजाना ईडी मुख्यालय में बिठाया जाता था और उनके बयानों को दर्ज किया जाता था। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त की गयी। संसद सदस्यता रद्द होने के महज तीन दिन बाद, 27 मार्च 2023 को लोकसभा की आवास समिति ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया। परन्तु राहुल गांधी ने किसी भी कानूनी विवाद में पड़े बिना 22 अप्रैल 2023 को 12, तुगलक लेन का अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया और अपनी मां सोनिया गांधी के घर शिफ़्ट हो गए। गोया हमेशा ही सत्ता व उसकी अधीन संस्थाओं द्वारा राहुल को दबाने व डराने की भरपूर कोशिश की गयी।

सपा का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहती कांग्रेस

@ अजय कुमार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राज्य की सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और 403 सीटों वाली इस विधानसभा में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर कानून-व्यवस्था, डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और लाभार्थी योजनाओं के जरिए अपनी जमीन को और मजबूत करने पर है, हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी के सामने अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करने तथा गैर-यादव ओबीसी और दलित मतदाताओं को एक बार फिर पूरी ताकत से अपने पाले में लाने की बड़ी चुनौती खड़ी है। वहीं दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की जुगत में हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पीडीए की अलग-अलग और कई बार बदली हुई परिभाषाओं के कारण मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति भी पैदा हुई है। इसके अलावा, सपा द्वारा ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिशों के बीच जब सवर्णों ने आरक्षण के मसले पर नाराजगी जाहिर की और अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया, तो अगड़े वोटर खासे नाराज नजर आए, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है।

इन तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद समाजवादी पार्टी टिकट वितरण और जमीनी स्तर पर खुद को मुख्य विपक्षी विकल्प के रूप में पेश करते हुए कई लोकलुभावन वादे कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते अखिलेश यादव के लिए इस पीडीए गठबंधन को अंत तक बचाए रखना और सीटों के तालमेल को संभालना एक बड़ी अग्निपरीक्षा साबित हो रहा है। इन सबके बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी अपने कोर जाटव वोट बैंक और बूथ स्तर के व्यापक बदलावों के दम पर 2007 के पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले (दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम) को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटी हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने पर विपक्ष के वोटों में बड़ी सेंध लग सकती है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तर प्रदेश को लेकर बनाई जा रही रणनीति बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों के बाद मिले सकारात्मक

संकेतों को आधार बनाते हुए यूपी में अपनी संगठनात्मक क्षमता को जमीन पर उतारने का जो ताना-बाना बुना है, उसमें राहुल गांधी की राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक न्याय की मुखर राजनीति और प्रियंका गांधी वाड्रा का जमीनी स्तर पर महिलाओं व युवाओं को सीधे जोड़ने वाला लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसी प्राथमिकताओं वाला एंगिल प्रमुख रूप से शामिल है।

कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बार केवल कागजी गठजोड़ तक सीमित रहने के बजाय ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन सृजन अभियान चलाकर अपनी पुरानी खोई हुई जमीन वापस पाने की फिराक में है। प्रियंका गांधी की यूपी की राजनीति में सक्रिय भूमिका और पर्दे के पीछे चल रही बैठकों के संकेत यह बताते हैं कि कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में खुद को महज एक पिछलग्गू दल के रूप में पेश करने के बजाय सम्मानजनक सीटों और मजबूत हिस्सेदारी के साथ मैदान में उतरना चाहती है। राहुल गांधी के संविधान बचाओ और पीडीए समर्थित जनादेश वाले मुद्दों को कांग्रेस कार्यकर्ता यूपी के गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी पर भी लगातार यह दबाव बना हुआ है कि वह गांधी परिवार और कांग्रेस को साथ लेकर चले ताकि विपक्षी मतों का बिखराव रोका जा सके। हालांकि, 202 सीटों के जादुई आंकड़े को पार कर बहुमत हासिल करने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी अपनी चुनावी मशीनरी को धार दे रही है, वहीं विपक्ष के खेमे में खासकर कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग का यह पेंच और राहुल-प्रियंका की जोड़ी का यूपी में आक्रामक प्रचार अभियान तय करेगा कि 2027 का यह दंगल वास्तव में किस करवट बैठेगा।

राहुल गांधी की राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक न्याय की मुखर राजनीति और प्रियंका गांधी वाड्रा का जमीनी स्तर पर महिलाओं व युवाओं को सीधे जोड़ने वाला लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसी प्राथमिकताओं वाला एंगिल प्रमुख रूप से शामिल है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बार केवल कागजी गठजोड़ तक सीमित रहने के बजाय ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन सृजन अभियान चलाकर अपनी पुरानी खोई हुई जमीन वापस पाने की फिराक में है।

सियासी चौराहे पर अखिलेश का 'पीडीए' प्रयोग

@ अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से नए नारों, अनूठे सामाजिक गठबंधनों और चौंकाने वाले वैचारिक मोड़ों के लिए जानी जाती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चर्चित राजनीतिक सूत्र 'पीडीए'की एक नई और भावनात्मक व्याख्या पेश की है। अगस्त 2026 के इस सियासी माहौल में, जब सभी दल भविष्य की रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की कि पीडीए का असली और मूल भावनात्मक सिद्धांत दरअसल 'प्रेम, दया और अपनापन' है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने तर्क दिया कि सत्ताधारी दल में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को स्थान तो मिल सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां इस भावनात्मक जुड़ाव की कमी है।

यह पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने अपने इस प्रिय नारे की री-ब्रांडिंग की है, अभी कुछ ही दिनों पहले, समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर उन्होंने राजनीति के पंडितों को चौंकाते हुए कहा था कि पीडीए में 'पीडी' का एक अर्थ 'पंडित' भी है। उस समय उन्होंने 'पी' से पीड़ित और पंडित,'डी' से दलित और 'ए' से आधी आबादी (महिलाएं)'अच्छे अगड़े' को जोड़कर एक नया 'पंडित फॉर्मूला' या 'ब्राह्मण कार्ड' खेलने का प्रयास किया था। राजनीति के एक बेहद सधे हुए व आक्रामक नारे को अचानक इस तरह के भावनात्मक सर्ववर्ण-समावेशी आवरण में लपेटने की यह कोशिश सहज नहीं दिखती। यह बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहे गहरे वैचारिक मंथन और साथ ही एक बड़ी रणनीतिक बेचैनी को भी रेखांकित करता है।

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस मूल राजनीतिक संदर्भ को याद करना होगा जहाँ से ढऊअ का जन्म हुआ था। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव ने 'पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक' के तौर पर पीडीए का नारा उछाला था। यह नारा विशुद्ध रूप से जातिगत और धार्मिक पहचान पर आधारित एक ठोस सामाजिक ब्लॉक बनाने की कोशिश थी। इसने सपा के पारंपरिक यादव-मुस्लिम (एम) समीकरण का दायरा बढ़ाकर गैर-यादव पिछड़ी जातियों को एक मंच पर लाने का काम किया था। लेकिन राजनीति कभी एक जगह ठहरती नहीं है। 2024 की सफलता के

बाद जैसे ही पार्टी आगामी राजनीतिक चुनौतियों की ओर बढ़ी, अखिलेश यादव को शायद इस बात का अहसास हुआ कि सिर्फ जातिगत ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता तक नहीं पहुँचा जा सकता।

इसके विपरीत, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजनीति हमेशा से जातियों के विभाजन से ऊपर उठकर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र पर आधारित रही है। भाजपा ने बिना किसी भेदभाव के हर जाति, वर्ग और संप्रदाय को मुख्यधारा से जोड़ा है। उज्ज्वला योजना, राशन वितरण, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ बिना किसी जातिगत चश्मे के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव को अब अपनी केवल 'पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक' वाली संकीर्ण छवि से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वे भाजपा की इसी सर्वसमावेशी विकास नीति की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं।

राजनीतिक नजरिए से देखें तो अखिलेश यादव का यह नया प्रयोग एक गंभीर वैचारिक अंतर्विरोध और राजनीतिक अवसरवाद को जन्म देता है। समाजवादी पार्टी पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक 'जाति जनगणना' और 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' के मुद्दे पर सबसे मुखर रही है। जाति जनगणना की मांग पूरी तरह से समाज को टुकड़ों में बांटने और सामाजिक विद्वेष फैलाने की राजनीति पर टिकी है। यह मांग मानती है कि समाज में संसाधनों और सत्ता का बंटवारा जातियों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए, जो सीधे तौर पर समाज के एक बड़े वर्ग को अलग-थलग करने की कोशिश है।

लेकिन, जब अखिलेश यादव अचानक इसी नारे को 'प्रेम, दया और अपनापन' जैसे बेहद भावुक शब्दों से परिभाषित करने लगते हैं, तो उनकी वैचारिक दुविधा साफ उजागर हो जाती है। सवाल यह उठता है कि जो पार्टी हर मंच पर खड़े होकर समाज को जातियों में बांटने और आंकड़ों की बात करती है, वह अचानक 'दया और अपनत्व' का स्वांग कैसे रच सकती है? क्या शोषित और पिछड़े वर्गों को केवल चुनाव के समय याद किया जाता है और बाद में सवर्णों को रिझाने के लिए परिभाषा बदल दी जाती है? यह विरोधाभास इसलिए भी गहरा है क्योंकि 'दया' हमेशा मजबूत व्यक्ति कमजोर पर दिखाता है। जब अखिलेश यादव 'डी' का मतलब 'दया' बताते हैं, तो वे अनजाने में ही दलितों और पिछड़ों को हकदार के बजाय 'दया का पात्र' बना देते हैं। एक तरफ जाति जनगणना के जरिए समाज में लकीर खींचना और दूसरी तरफ 'प्रेम और अपनत्व' के जरिए उसी लकीर को मिटाने का नाटक करना–सपा की रणनीति की इसी खोखली वैचारिक बुनियाद को दिखाता है।

इसीलिए अखिलेश यादव जब ढऊअ को 'प्रेम, दया और अपनापन' का नया आवरण देते हैं, तो उनका सामना उत्तर प्रदेश की जनता की यादों में दर्ज समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल से होता है। राजनीतिक विश्लेषक और आम जनता इस बात को भूली नहीं है कि सपा सरकार के दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था किस कदर चरमरा गई थी। उस दौर में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का मुहावरा चरितार्थ होता था, जहां संगठित अपराध, जमीनों पर कब्जे और दंगों का एक ऐसा माहौल था जिसने व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों को असुरक्षित महसूस कराया।

इसके विपरीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 'दंगा मुक्त' और सुरक्षित राज्य बनाकर एक नजीर पेश की है। भाजपा शासन ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई, जिसने राज्य में कानून का इकबाल बुलंद किया। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं रात में भी बेखौफ बाहर निकल सकती हैं, और उद्योगपति बिना किसी रंगदारी के डर के निवेश कर रहे हैं। ऐसे में, अखिलेश यादव का 'प्रेम और अपनापन' का यह नया नैरेटिव दरअसल सपा की उस पुरानी 'दबंगई और तुष्टिकरण' वाली छवि को धोने की एक हताश कोशिश नजर आता है। जनता यह बखूबी समझती है कि कानून-व्यवस्था केवल मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि एक मजबूत और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार के प्रशासनिक हंटर से सुधरती है, जो फिलहाल भाजपा के पास है।

इस वैचारिक भटकाव के पीछे समाजवादी पार्टी की कुछ व्यावहारिक मजबूरियां भी साफ नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, जिससे दलित मतों का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक ठिकाने की तलाश में है। अखिलेश यादव इस बड़े वर्ग को यह संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब केवल एक या दो जातियों की पार्टी नहीं है, बल्कि यहां उन्हें 'अपनापन' और सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही, भाजपा के उग्र राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पुनरुत्थान (जैसे भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण) और मजबूत कानून-व्यवस्था के एजेंडे की काट ढूंढना सपा के लिए असंभव साबित हो रहा है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को 'दंगा मुक्त' और सुरक्षित राज्य बनाया है, जिससे व्यापारी, महिलाएं और युवा खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस मजबूत प्रशासनिक छवि की काट के लिए सपा को एक ऐसा नैरेटिव चाहिए था जो बहुसंख्यक समाज (जिसमें सवर्ण भी शामिल हैं) को डराए या दूर न करे। 'प्रेम, दया और अपनापन' के जरिए अखिलेश दरअसल भाजपा के उस विकासवादी और सांस्कृतिक नैरेटिव को कुंद करना चाहते हैं जो विपक्षी गठबंधन को जातिवादी या तुष्टिकरण करने वाला बताता है। वे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर चल रही 'मोहब्बत की दुकान' वाली फ्लॉप राजनीति की तर्ज पर प्रादेशिक स्तर पर अपनी एक खोखली वैचारिक लाइन खींचना चाहते हैं।

कश्मीर पर अमेरिकी सुर बदले भारत का कद बढ़ा, पाक बेचैन

@ राष्ट्र समाज

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का 19 अगस्त 2026 को श्रीनगर में दिया गया यह बयान कि जम्मू-कश्मीर 'भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा' है, सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी मानकर नजर अंदाज करने योग्य नहीं है। यह ऐसे समय आया है जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की धारणाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार नए समीकरण बन रहे हैं। गोर ने जम्मू-कश्मीर की निरंतर सुधर रही सुरक्षा स्थिति की बात कही और अमेरिकी यात्रा संबंधी परामर्श पर पुनर्विचार के संकेत भी दिए। पाकिस्तान ने इस बयान पर अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को तलब कर तीखा विरोध दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम को केवल कश्मीर के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारत-अमेरिका संबंधों में आ रहे व्यापक परिवर्तन, दक्षिण एशिया की बदलती सामरिक संरचना और पाकिस्तान की घटती कूटनीतिक प्रभावशीलता के संदर्भ में समझना अधिक उचित होगा।

अमेरिका की कश्मीर नीति में लंबे समय से एक प्रकार की सावधानी रही है। वाशिंगटन सामान्यतः भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद तथा शांतिपूर्ण समाधान की बात करता रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की पूर्व घोषित नीति भी जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति और राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता की वापसी का समर्थन करती रही है। इसलिए गोर का श्रीनगर में जाकर जम्मू-कश्मीर को भारत का 'महत्वपूर्ण हिस्सा' कहना निश्चित रूप से भाषा के स्तर पर एक उल्लेखनीय परिवर्तन है। लेकिन इसे अमेरिका की पूरी कश्मीर नीति में तत्काल और औपचारिक परिवर्तन मानना भी जल्दबाजी होगी। किसी राजदूत का बयान और किसी सरकार की औपचारिक नीति में अंतर होता है। फिर भी कूटनीति में शब्दों का अपना महत्व होता है। विशेष रूप से तब, जब वही शब्द उस भूभाग में बोले जाएं जिसे पाकिस्तान दशकों से अंतरराष्ट्रीय विवाद के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। इस दृष्टि से गोर का बयान भारत के लिए मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है।

इस बयान का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जम्मू-कश्मीर की बदलती जमीन से जुड़ा है। गोर ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए यात्रा संबंधी अमेरिकी परामर्श में कमी लाने की संभावना जताई है। इसका अर्थ यह है कि वाशिंगटन अब कश्मीर को केवल सुरक्षा संकट या आतंकवाद की दृष्टि से देखने के बजाय पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और सामान्य जनजीवन की संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में

भी देख रहा है। यहीं से भारत-अमेरिका संबंधों की नई रोशनी दिखाई देती है। दोनों देशों के संबंध अब केवल व्यापार या रक्षा तक सीमित नहीं हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आपूर्ति-श्रृंखला और वैश्विक शक्ति-संतुलन जैसे विषयों ने भारत को अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार और शुल्क जैसे मुद्दों पर मतभेद भी मौजूद हैं, फिर भी व्यापक सामरिक साझेदारी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा का उद्देश्य भी तनावों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना और व्यापार तथा ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाना था।

कश्मीर पर अमेरिकी भाषा को भारत-अमेरिका संबंधों के व्यापक पुनर्संतुलन का हिस्सा मानना अधिक तार्किक होगा। अमेरिका के लिए भारत अब केवल दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति-संतुलन का प्रमुख आधार है। भारत के लिए भी अमेरिका महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को किसी एक शक्ति के साथ पूर्ण निर्भरता के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रखा है। यही कारण है कि भारत अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाते हुए रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया व अन्य शक्तियों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखता है। कश्मीर के संदर्भ में यह घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से असहज करने वाला है। इस्लामाबाद ने गोर के बयान को अस्वीकार करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और उसका अंतिम निर्धारण होना बाकी है। पाक ने इसे अमेरिका की पूर्व स्थिति से विचलन बताते हुए औपचारिक विरोध दर्ज कराया।

पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी विदेश नीति का केंद्रीय विषय बनाए रखना चाहता है, जबकि विश्व राजनीति की प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं। आतंकवाद, आर्थिक स्थिरता, चीन का बढ़ता प्रभाव, पश्चिम एशिया का संकट, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाएं आज बड़ी शक्तियों की चिंता के केंद्र में हैं। ऐसे वातावरण में केवल कश्मीर के प्रश्न को बार-बार अंतरराष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तानी कोशिशों की प्रभावशीलता सीमित होती जा रही है। भारत ने दूसरी ओर लगातार यह रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े विषय भारत की संप्रभुता और द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में आते हैं।

गोर का श्रीनगर दौरा स्वयं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एक प्रमुख अमेरिकी राजनयिक ने जम्मू-कश्मीर की यात्रा की, वहां के निर्वाचित नेतृत्व से मुलाकात की और क्षेत्र की सुरक्षा तथा आर्थिक संभावनाओं पर सकारात्मक टिप्पणी की। यह पाकिस्तान की उस कोशिश के विपरीत है जिसमें वह कश्मीर को केवल विवाद और अस्थिरता के चश्मे से प्रस्तुत करना चाहता है।

फिर भी भारत को इस बयान से अत्यधिक उत्साहित होकर यह मान लेने से बचना चाहिए कि अमेरिका ने कश्मीर पर अपनी संपूर्ण नीति बदल दी है। अमेरिका की विदेश नीति परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और वह भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित करने की कोशिश करता है। आज भी वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान आतंकवाद-रोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान सहित कुछ विषयों में उपयोगी साझेदार है।

अतः भारत के लिए इस बयान का वास्तविक महत्व किसी औपचारिक अमेरिकी नीति-परिवर्तन से अधिक उस कूटनीतिक वातावरण में है, जिसमें भारत की स्थिति को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। कूटनीति में किसी देश का महत्व केवल इस बात से तय नहीं होता कि कितने देश उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, बल्कि इससे तय होता है कि वैश्विक शक्तियों के हित उसके साथ कितने गहरे जुड़े हैं। आज भारत की आर्थिक क्षमता, विशाल बाजार, तकनीकी सामर्थ्य, लोकतांत्रिक संस्थाएं, युवा शक्ति और सामरिक स्थिति उसे विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती हैं। इसी बदलती वास्तविकता का प्रभाव कश्मीर पर भी दिखाई देना स्वाभाविक है।

गोर का बयान इसलिए भारत के लिए एक उपलब्धि से अधिक एक संकेत है-संकेत इस बात का कि जम्मू-कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय विमर्श धीरे-धीरे बदल रहा है। पाकिस्तान के लिए यह चेतावनी है कि केवल पुराने नारों और कूटनीतिक दबाव से वह कश्मीर को विश्व राजनीति के केंद्र में नहीं रख सकता और अमेरिका के लिए यह उसके बदलते हितों के अनुरूप संतुलन साधने की कोशिश है। अंततः कश्मीर की स्थायी शांति केवल अंतरराष्ट्रीय बयानों से नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विकास, सुरक्षा, जनभागीदारी और सीमा-पार आतंकवाद के अंत से सुनिश्चित होगी। भारत को इस नए कूटनीतिक वातावरण का उपयोग आक्रामक प्रचार के बजाय जिम्मेदार और आत्मविश्वासी राष्ट्र की तरह करना चाहिए।

चुनावी मूड में मायावती भतीजे को कमान

@ संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब छह माह का समय बचा है, इसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने अभी से जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर बीते कुछ हफ्तों में जो संगठनात्मक फेरबदल हुए हैं, उनसे साफ संकेत मिलता है कि बसपा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को संगठन और चुनाव प्रचार की अगुवाई सौंपी है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भरोसेमंद ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा का कद और बढ़ा दिया गया है। यह दोहरी रणनीति बसपा के सामाजिक समीकरण और पारिवारिक उत्तराधिकार, दोनों मोर्चों को साधने की कोशिश मानी जा रही है।

बसपा में उत्तराधिकार को लेकर पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। एक समय मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, फिर विवादों के चलते उन्हें पार्टी पदों से हटाया भी गया। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टी ने उन्हें फिर से सक्रिय भूमिका में ला खड़ा किया है। अब आकाश आनंद राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर सक्रिय हैं और उन्हें प्रत्याशियों के चयन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी अगुवाई में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलनों में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। इस नई भूमिका के तहत आकाश आनंद ने 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद से अपने अभियान की शुरूआत की।

इसके बाद 25 अगस्त को गौतमबुद्ध नगर के जेवर में भी उनकी अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होना तय है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ में हुई तीन दिवसीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि आकाश आनंद को अब यूपी और उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका दी जाए, जबकि पहले उन्हें इन राज्यों की राजनीति से जानबूझकर दूर रखा गया था। पार्टी पदाधिकारियों का मानना है कि प्रचार अभियान की कमान संभालने से आकाश आनंद का सियासी कद और मजबूत होगा।

हालांकि मायावती ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि टिकट बंटवारे का अंतिम और सर्वोच्च फैसला सिर्फ वही लेंगी। इसमें आकाश आनंद की कोई निर्णायक भूमिका नहीं होगी। राजनीतिक हलकों में इस बयान को शक्ति-संतुलन बनाए रखने की एक सोची-समझी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब साफ है कि प्रचार और संगठन की जिम्मेदारी भतीजे को, लेकिन असली सत्ता की डोर अभी भी मायावती के हाथ में ही रहेगी। इसी बीच बसपा ने एक और अहम संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की

जिम्मेदारियां और बढ़ा दी गई हैं। अब वे कानूनी और मीडिया से जुड़े कामकाज के साथ-साथ चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। मायावती ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत पार्टी का जनाधार सभी वर्गों में मजबूत किया जा रहा है, साथ ही प्रत्याशियों के चयन और उनकी घोषणा की प्रक्रिया भी विधानसभा-स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए चल रही है। उन्होंने दावा किया कि बसपा की इन तैयारियों से विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ गई है।

सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई यह नई जिम्मेदारी अचानक नहीं आई है। बसपा के लिए ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से एक अहम सामाजिक समीकरण रहा है, और मिश्रा दशकों से इस समीकरण के केंद्र में रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी के कई कद्दावर ब्राह्मण नेता एक-एक कर साथ छोड़ते गए हैं। पूर्व मंत्री नकुल दुबे 2022 में कांग्रेस में चले गए, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, रंगनाथ मिश्रा और विनय शंकर तिवारी जैसे नेता भी पार्टी से दूर हो चुके हैं। हाल ही में बसपा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को भी पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अंटू मिश्रा को सतीश चंद्र मिश्रा का करीबी माना जाता रहा है, और चर्चा यह भी थी कि वे चुनाव से पहले किसी दूसरे दल का रुख कर सकते हैं। इन घटनाक्रमों के बीच बसपा की सियासी नर्सरी से ब्राह्मण नेताओं का लगातार खिसकना पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में मायावती का सतीश मिश्रा पर भरोसा जताना और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाना, इस बिखराव को थामने और बचे-खुचे ब्राह्मण जनाधार को एकजुट रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी अब पूरी तरह से मिश्रा के चेहरे और उनके संगठनात्मक अनुभव पर दांव लगाना चाहती है, ताकि सर्व समाज के जनाधार वाली अपनी पुरानी छवि को दोबारा मजबूत किया जा सके।

दोहरी रणनीति के मायने

मायावती की यह दोहरी रणनीति एक तरफ पारिवारिक उत्तराधिकार को संस्थागत रूप देना, दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों को संभालने के लिए अनुभवी चेहरों को आगे रखना और बसपा के भविष्य की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। आकाश आनंद के जरिए पार्टी युवा और सक्रिय नेतृत्व का संदेश देना चाहती है, जबकि सतीश मिश्रा के जरिए पार्टी अपने परंपरागत सामाजिक आधार और अनुभव को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा के लिए 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि पार्टी के अस्तित्व से जुड़ा सवाल भी है। बीते कुछ चुनावों में लगातार कमजोर होते प्रदर्शन के बाद पार्टी को अपने कोर वोट बैंक के साथ-साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने की जरूरत है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद की सक्रियता और सतीश चंद्र मिश्रा की नई भूमिका मिलकर बसपा के जनाधार को कितना विस्तार दे पाती है, और क्या पार्टी विरोधी दलों की उस बेचैनी को हकीकत में बदल पाती है, जिसका दावा मायावती खुद कर रही हैं।

@ राष्ट्र समाज

झारखंड सरकार ने छात्रों की सभी मांगें मानी

झारखंड में छात्रों के चौतरफा और ऐतिहासिक आंदोलन के आगे आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार झुक गई है और उसने राज्य की सबसे विवादित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने के साथ ही साल 2014 से अब तक निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की एक मैराथन बैठक बुलाई और इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी। छात्रों की इस अभूतपूर्व जीत के बाद राज्य भर के परीक्षा केंद्रों और प्रदर्शन स्थलों पर जश्न का माहौल है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा पेंच अभी भी फंसा हुआ है। छात्र संगठन इस पूरे घोटाले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे राज्य सरकार ने फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस पूरे मामले की कमान राज्य की अपराध अनुसंधान विभाग और विशेष जांच दल को सौंपते हुए वर्ष 2014 से हुई गड़बड़ियों की व्यापक जांच का आदेश दिया है, लेकिन वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करने से साफ बच रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार को डर है कि अगर यह जांच सीबीआई के हाथों में चली गई, तो जांच की आंच सीधे सरकार के शीर्ष अधिकारियों और सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाएगी, जिससे उनकी राजनीतिक गर्दन पूरी तरह से दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के हाथों में आ जाएगी।

इस पूरे विवाद की जड़ में वह परीक्षाएं हैं, जिन्हें लेकर पिछले कई महीनों से राज्य का युवा सड़कों पर उतरा हुआ था। छात्रों के भारी दबाव के बाद झारखंड सरकार ने जिन प्रमुख परीक्षाओं को रद्द किया है, उनमें सबसे बड़ी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा शामिल है।इसके अलावा, एक विवादित और दागी आउटसोर्सिंग एजेंसी 'टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड' (टीडीपीएल) के जरिए वर्ष 2014 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, उनके परिणाम जारी हुए थे या जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उन सभी प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इससे पहले ही छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 और 2025 में आयोजित जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया था। इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक होने,

डिजिटल धांधली करने और पैसों के लेन-देन के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद तीन जेपीएससी सदस्यों को अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ा था। सरकार ने अब परीक्षाओं के आयोजन में सुधार लाने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन भी कर दिया है।

पिछले 24 दिनों का घटनाक्रम झारखंड के इतिहास में युवाओं के सबसे बड़े और संगठित विद्रोह की कहानी बयां करता है। आंदोलन की शुरूआत जुलाई के आखिरी हफ्तों में हुई थी, जब जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के आयोजन और उसके नतीजों में भारी विसंगतियां और धांधली के सबूत सोशल मीडिया पर तैरने लगे थे। इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रांची की सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस आंदोलन ने एक उग्र रूप ले लिया और छात्र नेताओं ने जयपाल सिंह स्टेडियम और अन्य प्रमुख स्थलों पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पिछले दो हफ्तों से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और राहुल क्रांति समेत कई अन्य अभ्यर्थी आमरण अनशन

पर बैठ गए थे। भूख हड़ताल की वजह से कई छात्रों की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बावजूद छात्रों का हौसला नहीं डगमगाया और उन्होंने सरकार से साफ कह दिया कि जब तक परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी और पारदर्शी जांच की गारंटी नहीं मिलेगी, वे पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने और राज्य विधानसभा तक एक विशाल पैदल मार्च निकालने का भी एलान कर दिया था, जिसने सोरेन सरकार के भीतर एक राजनीतिक घबराहट पैदा कर दी थी।

आंदोलन के बढ़ते दबाव और छात्रों की बिगड़ती सेहत को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने मंत्रियों के साथ एक आपातकालीन बैठक करनी पड़ी। इस बैठक में राज्य के खुफिया इनपुट और पुलिस विभाग की रिपोर्ट को सामने रखा गया, जिसमें यह साफ हो गया था कि छात्रों का यह गुस्सा राज्य सरकार के लिए आगामी चुनावों में भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर घोषणा की कि सीआईडी और एसआईटी की जांच में कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें इस मोड़ पर उजागर नहीं किया जा सकता। उन्होंने माना कि परीक्षाओं का संचालन करने वाली बाहरी एजेंसियां एक बड़े रैकेट का हिस्सा हैं, जो झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थीं। सरकार ने तुरंत टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट करते हुए उसके द्वारा कराए गए पिछले दस साल के सभी कामों को शून्य घोषित कर दिया। मंत्रियों की मौजूदगी में अस्पताल में भर्ती अनशनकारी छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया गया, जिसे छात्र संगठनों ने अपनी आधी ऐतिहासिक जीत माना।

हालांकि, परीक्षाओं के रद्द होने से आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसने एक नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। छात्र संगठन और विपक्षी दल अब भी इस बात पर अड़े हैं कि राज्य की सीआईडी या एसआईटी इस विशाल सिंडिकेट और उसके असली सरगनाओं को कभी नहीं पकड़ पाएगी। छात्रों का तर्क है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई नहीं करेगी, तब तक पर्दे के पीछे बैठे असली 'मास्टरमाइंड' और सफेदपोश राजनेता कभी बेनकाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीबीआई जांच से इनकार करना उनकी राजनीतिक मजबूरी और केंद्रीय एजेंसियों के डर को दर्शाता है। सोरेन सरकार का मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी दलों को कुचलने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में करती रही है। मुख्यमंत्री खुद भूमि घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद महीनों जेल में बिताकर हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं। ऐसे में वे भली-भांति जानते हैं कि अगर उन्होंने इस परीक्षा घोटाले की चाबी सीबीआई को सौंप दी, तो केंद्र सरकार इस जांच का दायरा बढ़ाकर उनके करीबियों और सरकार के मंत्रियों तक पहुंचा देगी, जिससे पूरी सरकार संकट में आ सकती है।

कहीं ऐसा तो नहीं कि न सिर्फ सत्ता में बैठी भाजपा बल्कि उसके दबाव में संघ परिवार का बड़ा हिस्सा ही, आरएसएस प्रमुख के विचारों से दूर चला गया हो? तत्काल कम से कम तीन प्रसंग ऐसे याद आते हैं, जिनमें स्वयंसंघ प्रमुख भागवत वर्तमान शासन और संघ परिवार को, न्यूयार्क के उनके उपदेश से ठीक उल्टी दिशा में धकेलने की अगुआई करते हुए दुनिया ने देखा था।

अमेरिका में भागवत: विवेकानंद नंबर टू या...

@ राजेंद्र शर्मा

अगर कोई हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमान रहें ही नहीं, तो वह हिंदू रहेगा ही नहीं। और यह भी कि, 'अगर कोई खुद को हिंदू कहता है, तो उसे यह मानना होगा कि रास्ते (पूजा पद्धतियां) अलग-अलग हैं, पर एक ही लक्ष्य को जाते हैं। 'हिंदू की यह परिभाषा और पहचान, किसी और ने नहीं, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने न्यूयार्क के अपने दौरे पर पेश की है। जाहिर है कि हिंदू और हिंदुत्व की इस तरह की उदार परिभाषा पेश करने के जरिए, संघ प्रमुख न सिर्फ आरएसएस की बल्कि उसके द्वारा सख्ती से नियंत्रित मोदी शासन की भी, इसके लिए दुनिया भर में हो रही आलोचनाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे कि वे असल में हिंदू सर्वोच्चतावादी राज और राजनीति के प्रतिनिधि हैं, जो हर प्रकार के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की दुश्मन है।

बहरहाल पश्चिम में आरएसएस-मोदी राज के धर्मनिरपेक्ष मेकओवर की यह कोशिश, कारगर होती नजर नहीं आती है। इसकी मोटे तौर पर दो बड़ी वजहें हैं। पहली तो यही कि यह कोशिश बढ़ती संख्या में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक अधिकार तथा मानवाधिकार संगठनों ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों द्वारा भी, मोदी के राज में धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत विभिन्न कमजोर तबकों के साथ बढ़ते भेदभाव तथा उनके अधिकारों पर बढ़ते हमलों की, एक के बाद लगातार आ रही रिपोर्टों के दबाव में की जा रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआई आरएफ) के मोदी राज को साल दर साल धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के पहलू से 'गंभीर चिंताइ का विषय घोषित करने और हर बार अमेरिकी सरकार पर इस सिलसिले में भारत पर दबाव डालने के लिए पाबंदियां लगाने की मांग करने के बाद, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की कमेटी ऑन एलीमिनेशन आफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन (सीईआरडी) ने भी अपनी समीक्षा रिपोर्ट में, भारत की स्थिति को 'गंभीर चिंताइ का विषय कहा है।

परदेश में मोदी राज और उसके वाहक के रूप में आरएसएस के इस मेकओवर के लोगों को भ्रमित न कर पाने की और भी बड़ी वजह, इस राज तथा आरएसएस का वास्तविक आचरण है, जो आरएसएस के मेकओवर की इस कोशिश को, एक भोंडे प्रहसन में तब्दील कर देती है। यह संयोग ही नहीं है कि ठीक उस समय जब मोहन भागवत अमेरिका में यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो सर्वसमावेशी है, ठीक उसी समय सत्ताधारी भाजपा का आईटी सेल, देश में एक ऐसा नया आक्रामक वीडियो रील अभियान छेड़ रहा था, जिसकी एक और सिर्फ एक ही थीम है–विरोधियों के खिलाफ भयानक हिंसा। लेकिन, सत्ताधारी पार्टी के प्रचार आह्वान में हिंसा के स्वर का बढ़ना ही,

अकेला बदलाव नहीं था जो भारत में ठीक उसी समय हो रहा था, अमेरिका में भागवत एक झूठा उदार मुखौटा लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब अमेरिका में भागवत यह कह रहे थे कि 'अगर कोई हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमान रहें ही नहीं, तो वह हिंदू रहेगा ही नहीं' ठीक उसी समय भाजपा-शासित उत्तराखंड और ओडिशा से इसकी रिपोर्टें आ रही थीं कि किस तरह, इस दौरान जारी एसआईआर की प्रक्रिया को, टार्गेट कर के मतदाता सूचियों से मुसलमानों के नाम काटे जाने के मौके में तब्दील किया जा रहा है। उधर चंद महीने पहले संघ-भाजपा द्वारा फतेह किए गए प. बंगाल में, एक ओर चर्चों तथा पादरियों पर हिंसक हमलों की शुरूआत हो रही थी और दूसरी ओर, दुर्गा पूजा के बंगाली प्रभावों से 'शुद्धीकरणइ की मुहिम छेड़ी जा रही था।

जब भागवत इसका उपदेश कर रहे थे कि, 'हरेक मनुष्य की गरिमा का सम्मान होना चाहिए,' ठीक तभी उनके संघ पोषित राज में उत्तराखंड में, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के दलित होने के कारण, उनकी सभा के बाद सभा मंच का बाकायदा यज्ञ कर के 'शुद्धीकरण' किए जाने के बाद, सत्ताधारी पार्टी के नेतागण उसका बचाव करने से लेकर, उसे झुठलाने तक में लगे हुए थे, जबकि देश के कानून के अनुसार यह संज्ञेय अपराध है। और जब भागवत अमेरिकी श्रोताओं को यह भरोसा दिला रहे थे कि उनके विचार परिवार की नजरों में 'सब मनुष्य समान हैं', उसके आस-पास संसद में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी के महिला स्वतंत्रता के पक्ष में बोलते हुए, 'पितृसत्ता' पर हमला करने और उसे सैद्धांतिक-धार्मिक वैधता देने के लिए 'मनुस्मृति' की आलोचना करने के लिए, सत्ता में बैठे भागवत अनुयायी, महिलाओं और शूद्रों की पूर्ण अधिकारहीनता की पैरवी करने वाली इस नियमावली का हिंदू-धार्मिक ग्रंथ कहकर बचाव ही नहीं कर रहे थे, इस आलोचना को हिंदुओं पर हमला बताकर, इस बहस को भी सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे थे। कहने की जरूरत नहीं है कि इन और ऐसे सभी मामलों में संघ की सेनाएं, जमीन पर भारत में और वास्तव में एक हद तक तो अमेरिका समेत पश्चिम में भी, उन तमाम उदार आदर्शों के खिलाफ युद्ध ही छेड़े रही हैं, जिनका उपदेश भागवत संघ के मेकओवर के लिए कर रहे थे और भागवत ने कभी उन्हें टोका हो, इसके कोई साक्ष्य नहीं हैं।

कहीं ऐसा तो नहीं कि न सिर्फ सत्ता में बैठी भाजपा बल्कि उसके दबाव में संघ परिवार का बड़ा हिस्सा ही, आरएसएस प्रमुख के विचारों से दूर चला गया हो? तत्काल कम से कम तीन प्रसंग ऐसे याद आते हैं, जिनमें स्वयंसंघ प्रमुख भागवत वर्तमान शासन और संघ परिवार को, न्यूयार्क के उनके उपदेश से ठीक उल्टी दिशा में धकेलने की अगुआई करते हुए दुनिया ने देखा था। पहला प्रसंग, मोदी राज के शुरूआती दौर का है, जब गो-गुंडों की मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू ही हो रहा था। 6 अगस्त 2016 को दिल्ली में एक आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी ने इसके खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए, कहा था कि बहुत से लोग दिन में गोरक्षक बन जाते हैं और रात को अपराध करते हैं। उन्होंने राज्यों से उनसे सख्ती से निपटने का आग्रह भी किया था। अगले दिन, तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने यही बात दोहरायी थी।

लेकिन, उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर मौन साध लिया और साल भर बाद, बापू से जुड़े साबरमती आश्रम की शताब्दी के एक आयोजन में काफी दबे शब्दों में इसकी शिकायत की कि गोभक्ति के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं जो स्वीकार्य नहीं है। ऐसी हिंसा को गांधी जी ने मंजूर नहीं किया होता। हुआ यह था कि प्रधानमंत्री के शुरूआती बयानों के बाद, खुद मोहन भागवत ने सार्वजनिक बयान देकर, कथित गोरक्षकों का यह कहकर बचाव किया था कि उनमें ज्यादातर 'अच्छा काम' कर रहे थे। मोदी ने फौरन पांव पीछे खींच लिए और उसके बाद न उन्हें गोरक्षकों की हिंसा दिखाई दी और न किसी भाजपा सरकार ने ऐसे मामलों में कोई खास कार्रवाई की।

इसी प्रकार, 2018 के अपने दशहरा संबोधन में, मोहन भागवत ने मोदी सरकार से मांग की थी कि अब अदालत के फैसले की जरूरत नहीं है, संसद से कानून बनाकर राम मंदिर बनाया जाए। बाद में नवंबर के आखिर में हुई विहिप की हुंकार रैली में उन्होंने फौरन मंदिर बनाने की मांग को और बढ़ाया। याद रहे कि 2019 की दूसरी तिमाही में चुनाव होने थे। 2019 के नवंबर तक, सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के पक्ष में निर्णय आ चुका था। इसके बाद भी, 'मथुरा-काशी बाकी हैइ के नारे पर अपने एक बहुप्रचारित लंबे साक्षात्कार में भागवत ने यह तो कहा था कि आरएसएस इन्हें लेकर आंदोलन नहीं चलाने जा रहा है, लेकिन इसके साथ यह भी जोड़ दिया था कि आरएसएस के सदस्य निजी हैसियत से इन आंदोलनों में शामिल हो सकते हैं! साफ है कि भागवत और उनका संगठन, सक्रिय रूप से वर्तमान हुकूमत को, बहुसंख्यकवादी तानाशाही के रास्ते पर धकेलने में ही लगे रहे हैं और पश्चिम में अब जो बतकही कर रहे हैं, शुद्ध पाखंड है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष आयोजन के बहाने से, संघ प्रमुख भागवत ने अमेरिका में सार्वभौम एकात्मता या यूनिवर्सल वननैस के अपने उपदेश के जरिए, विवेकानंद-टू बनना चाहा है। न्यूयार्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डेन सभागार में भागवत का करीब पौने घंटे का व्याख्यान ही इस दौरे का मुख्य ईवेंट था। लेकिन, इस आयोजन में अगर करीब पांच हजार लोग, जिनमें जाहिर है कि प्रचंड बहुमत प्रवासी भारतीयों का था, श्रोताओं के रूप में शामिल हुए थे, तो सैकड़ों की संख्या में लोग, जिनमें भी प्रवासी भारतीयों की ही संख्या ज्यादा थी, विरोध जताने के लिए आयोजन स्थल के बाहर भी जमा हुए थे।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

दुनिया जब बुरे दौर में है तब भारत के आर्थिक उजाले

महंगाई, ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पथ मजबूत बना रहा। पिछले वर्ष इसी तिमाही में विकास दर 6.9 प्रतिशत थी। यानी एक वर्ष में आर्थिक वृद्धि की गति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है।

@ राष्ट्र समाज

दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है, वह आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से असाधारण चुनौतियों का दौर है। रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव, पश्चिम एशिया में तनाव, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने कठिन प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस मजबूती का परिचय दिया है, वह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलते भारत की सामर्थ्य का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को ऐसी उम्मीद के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी ओर दुनिया आश्चर्य और विश्वास दोनों के साथ देख रही है। इस विकास दर ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक शक्ति और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है एवं एक उजाला बिखेरा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वृद्धि ऐसे समय दर्ज हुई है, जब परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। महंगाई, ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पथ मजबूत बना रहा। पिछले वर्ष इसी तिमाही में विकास दर 6.9 प्रतिशत थी। यानी एक वर्ष में आर्थिक वृद्धि की गति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है। घरेलू मांग की मजबूती, सरकारी पूंजीगत व्यय, विनिर्माण, निर्माण और निर्यात जैसे क्षेत्रों का योगदान इस प्रदर्शन के पीछे महत्वपूर्ण रहा है।

आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है, जब उसे उसके वैश्विक संदर्भ में देखा जाए। आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं केवल आर्थिक नीतियों से प्रभावित नहीं हो रहीं, बल्कि युद्ध, कूटनीतिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंध भी उनकी दिशा तय कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का तनाव ऊर्जा बाजार और वैश्विक आपूर्ति तंत्र के लिए चिंता पैदा करता है। इन परिस्थितियों में भारत का अपेक्षाकृत तेज आर्थिक विकास यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए ऐसे मजबूत घरेलू आधार तैयार किए हैं, जो बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखते हैं। यही वह परिवर्तन है जो भारत को केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है। करोड़ों उपभोक्ताओं की मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, बुनियादी ढांचे पर निवेश और बदलती उपभोग संस्कृति ने अर्थव्यवस्था को आंतरिक गति प्रदान की है। जब वैश्विक बाजार अनिश्चित हों, तब घरेलू मांग अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा-कवच का काम करती है। इसीलिए वर्तमान विकास दर में घरेलू मांग की मजबूती को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

इस आर्थिक प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण

विशेषता यह भी है कि वृद्धि केवल एक क्षेत्र के सहारे नहीं टिकी है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारत धीरे-धीरे उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः सेवा क्षेत्र की शक्ति के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब देश में उत्पादन बढ़ाने, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में किए गए प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। निर्माण क्षेत्र भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, आवास, औद्योगिक गलियारे और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश का प्रभाव केवल आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, बल्कि उससे भविष्य की आर्थिक क्षमता भी निर्मित होती है।

भारत की वर्तमान आर्थिक यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई नीतियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, विनिर्माण, नए उद्यम, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया है। जनधन खातों से लेकर डिजिटल भुगतान तक और राजमार्गों से लेकर रेलवे के आधुनिकीकरण तक, आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक तंत्र तैयार हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर ने देश के बड़े बाजार को अधिक एकीकृत करने में भूमिका निभाई है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसी व्यवस्थाओं ने कारोबारी वातावरण को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने अनेक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और निवेश को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों का वास्तविक मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके परिणामों से होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत अवश्य देते हैं।

आम नागरिक के लिए आर्थिक विकास का अर्थ तभी सार्थक है, जब उसके जीवन में रोजगार के अवसर बढ़ें, आय में वृद्धि हो, महंगाई नियंत्रित रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार आए। सकल घरेलू उत्पाद हमें अर्थव्यवस्था की गति बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उस विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक किस प्रकार पहुंच रहा है। इसलिए भारत की अगली चुनौती तेज विकास से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी रोजगार है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का विस्तार इसलिए आशाजनक है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भविष्य में भारत को ऐसे उद्योगों की आवश्यकता होगी, जो बड़ी संख्या में युवाओं को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार दे सकें। भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि उसे कौशल, शिक्षा, तकनीक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं तो यही युवा शक्ति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी ऊर्जा बन सकती है।

भारत का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर बनना नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत करना है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके। आज दुनिया चीन के विकल्प के रूप में विभिन्न उत्पादन केंद्रों की तलाश कर रही है। भारत के पास विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, तकनीकी क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी विशिष्ट ताकतें हैं। यदि भारत विनिर्माण, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं में अपनी क्षमता बढ़ाता है, तो वह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। 2047 का विकसित भारत केवल सरकार का संकल्प नहीं, बल्कि देशवासियों की सामूहिक आकांक्षा है। 7.8 प्रतिशत की विकास दर इस यात्रा में एक उत्साहजनक पड़ाव है, मंजिल नहीं। भारत को लगातार उच्च विकास दर, मजबूत वित्तीय व्यवस्था और स्थिर आर्थिक वातावरण के साथ-साथ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर भी समान ध्यान देना होगा। भारत की आर्थिक कहानी अब केवल आंकड़ों की कहानी नहीं रह गई है। यह आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की कहानी बन रही है। दुनिया जब युद्ध और आर्थिक अस्थिरता की छाया में अपनी दिशा तलाश रही है, तब भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन उसे एक भरोसेमंद और संभावनाशील शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। 7.8 प्रतिशत की विकास दर निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने यह संदेश दिया है कि वैश्विक संकटों के बीच भी उसकी आर्थिक बुनियाद मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आर्थिक नीतियों और योजनाओं को अब अगले चरण में अधिक रोजगार, अधिक निवेश, अधिक उत्पादन और अधिक समान अवसरों से जोड़ना होगा। भारत के आर्थिक आकाश पर उगता यह उजाला तभी स्थायी प्रकाश बनेगा, जब विकास की रोशनी देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन तक पहुंचे। यही 2047 के विकसित भारत की वास्तविक कसौटी होगी और यही आर्थिक शक्ति को जनशक्ति में बदलने का मार्ग भी।

स्वास्थ्य क्रांति का नया अध्याय

गरीब और निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों के लिए गंभीर बीमारी केवल चिकित्सकीय संकट नहीं होती; वह आर्थिक संकट भी बन जाती है। किसी मरीज को कैंसर,हृदय रोग, किडनी की गंभीर बीमारी या किसी जटिल सर्जरी के लिए महानगर में जाना पड़े, तोअस्पताल का बिल केवल समस्या का एक हिस्सा होता है।

@ राष्ट्र समाज

वैश्विक स्तर पर 21वीं सदी में चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी ऊँचाइयाँ हासिल कर ली हैं,जिनकी कल्पना कुछ दशक पहले तक असंभव मानी जाती थी। जटिल सर्जरी,अत्याधुनिक कैंसर उपचार, अंग प्रत्यारोपण रोबोटिक तकनीक और जीवनरक्षक दवाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को नई उम्मीद दी है। लेकिन इसवैज्ञानिक उपलब्धि के समानांतर एक गंभीर मानवीय प्रश्न आज भी पूरी दुनियां के सामने खड़ा है,क्या इलाज उपलब्ध होने मात्र से स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है? यदि किसी गरीब परिवार को अस्पताल में उपचार तो मिल जाए, लेकिन इलाज के दौरान रहने,भोजन,परिवहन,कागजी प्रक्रिया और देखभाल के खर्च के कारण वह कर्ज में डूब जाए,तो क्या इसे पूर्ण स्वास्थ्य न्याय कहा जा सकता है? यही वह बिंदु है जहां दिनांक 23 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर प्रस्तावित सरकार, धमार्दाय/निजी अस्पतालों और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय सामंजस्य करार का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। यह पहल केवल चिकित्सा खर्च को कम करने की अवधारणा नहीं है,बल्कि मरीज के साथ आने वाले परिवार की सामाजिक, आर्थिक और मानवीय सुरक्षा को स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा मानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोच प्रस्तुत करती है।

इस मॉडल को भारत के हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं दुनिया के हर देश ने अपनाना चाहिए क्योंकि विश्व स्तरपर स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला निजी खर्च है। गरीब और निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों के लिए गंभीर बीमारी केवल चिकित्सकीय संकट नहीं होती; वह आर्थिक संकट भी बन जाती है। किसी मरीज को कैंसर,हृदय रोग, किडनी की गंभीर बीमारी या किसी जटिल सर्जरी के लिए महानगर में जाना पड़े, तो अस्पताल का बिल केवल समस्या का एक हिस्सा होता है। परिवार को कई सप्ताह या महीनों तक किराये का कमरा, भोजन, स्थानीय परिवहन, जांचों के लिए आवाजाही और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करना पड़ सकता है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले परिवारों के लिए यह बोझ और भी गंभीर हो जाता है। अनेक मामलों में मरीज के इलाज की व्यवस्था किसी सरकारी योजना या अस्पताल की रियायत से हो जाती है, लेकिन तीमारदारों की बुनियादी जरूरतें अनदेखी रह जाती हैं। यही वह खाली स्थान है जिसे महाराष्ट्र का त्रिपक्षीय मॉडल भरने की सटीकता से कोशिश करता है। साथियों बात अगर हम इस मॉडल को समझने की करें तो इस मॉडल की मूल शक्ति इसकी त्रिपक्षीय संरचना में है। पहला स्तंभ राज्य सरकार है, जो नीति, वित्तीय सहायता, डिजिटल सत्यापन, निगरानी और जवाबदेही का ढांचा तैयार करती है। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष जैसे तंत्र का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को सरकारी चिकित्सा सहायता तक पहुंचाने में मदद करना है। दूसरा स्तंभ धमार्दाय अथवा निजी अस्पताल हैं,जिनके पास विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू व जटिल उपचार की क्षमता उपलब्ध है। तीसरा और सबसे मानवीय स्तंभ स्वयंसेवी संस्थाएं तथा चैरिटेबल संगठन (एनजीओस) हैं, जो मरीज और उसके परिवार को अस्पताल के बाहर की उन जरूरतों से जोड़ सकते हैं जिन्हें पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था अक्सर नजरअंदाज कर देती है। इस प्रकार सरकार की नीति, अस्पताल की चिकित्सा क्षमता व नागरिक समाज की मानवीय संवेदना एक साझा व्यवस्था में जुड़ती है।

साथियों, इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार यह है कि स्वास्थ्य सेवा को केवल अस्पताल के भीतर होने वाली चिकित्सा प्रक्रिया नहीं माना जाता।किसी गरीब परिवार के लिए अस्पताल तक पहुंचना ही एक चुनौती हो सकता है। महानगर में पहुंचने के बाद सही विभाग ढूंढना, डॉक्टर तक पहुंचना,सरकारी सहायता के दस्तावेज तैयार करना,जांचों की तारीख समझना,दवाओं की व्यवस्था करना और रहने-खाने की समस्या से निपटना अलग- अलग कठिनाइयां हैं। यदि एक पंजीकृत और जवाबदेह एनजीओस मरीज के परिवार के लिए हेल्थ नेविगेटर की भूमिका निभाए,तो वह परिवार को व्यवस्था के भीतर रास्ता दिखा सकता है। इस व्यवस्था में विश्राम गृह, कम लागत या मुफ्त भोजन, स्थानीय परिवहन

संबंधी सहायता, दस्तावेजी मार्गदर्शन और मानसिक संबल जैसी सेवाएं शामिल की जा सकती हैं। इससे उपचार की वास्तविक पहुंच केवल कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत हो सकती है।

साथियों इसे एक उदाहरण के रूप में ऐसा समझा जा सकता है कि कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र के किसी दूरस्थ गांव का एक गरीब परिवार अपने आठ वर्षीय बच्चे को लेकर मुंबई या पुणे के किसी बड़े अस्पताल पहुंचता है। बच्चे को गंभीर हृदय रोग है और लंबे उपचार की आवश्यकता है।पारंपरिक व्यवस्था में परिवार को इलाज की आर्थिक चिंता के साथ महानगर में रहने का संकट भी झेलना पड़ सकता है।लेकिन यदि एक प्रभावी त्रिपक्षीय प्रणाली पहले से सक्रिय हो,तो मरीज का सरकारी सहायता के लिए डिजिटल सत्यापन, अस्पताल में उपचार की उपलब्धता और परिवार के लिए सुरक्षित आवास एवं भोजन एक समन्वित प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। इससे परिवार को अलग-अलग संस्थाओं के चक्कर लगाने के बजाय एकीकृत सहायता मिल सकती है। इस उदाहरण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा का अर्थ केवल मरीज को ऑपरेशन टेबल तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे उपचार की पूरी यात्रा सुरक्षित और गरिमापूर्ण तरीके से पूरी करने में सटिका से सक्षम बनाना है।

साथियों, इस मॉडल का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम धमार्दाय अस्पतालों और सामाजिक संसाधनों का बेहतर उपयोग है।भारत के अनेक हिस्सों में ऐसे अस्पताल और ट्रस्ट मौजूद हैं जिन्हें सार्वजनिक हित, धमार्दाय गतिविधियों या रियायती सरकारी सुविधाओं के आधार पर सामाजिक दायित्व निभाने होते हैं। यदि गरीब मरीजों के लिएनिर्धारित सेवाओं की पारदर्शी निगरानी हो, डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जाएं और पंजीकृत एनजीओस को सामाजिक ऑडिट तथा सहायता व्यवस्था में जिम्मेदार भूमिका दी जाए, तो उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।इसका अर्थ केवल अधिक मुफ्त बेड उपलब्ध कराना नहीं है;इसका अर्थ है कि जिस सामाजिक दायित्व के लिए संस्थागत सुविधाएं विकसित हुई हैं, उसका वास्तविक लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे।

साथियों तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र बिचौलियों औरअनधिकृत दलालों की भूमिका को कम करना है।बड़े अस्पतालों के आसपास आने वाले ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर मरीज अक्सर जानकारी की कमी के कारण गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। उन्हें महंगी एम्बुलेंस,अनावश्यक जांच,संदिग्ध दवाओं अथवा गैरजरूरी सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। यदि सरकारी सहायता, अस्पताल की सेवाएं और पंजीकृत एनजीओस की सहायता एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली से जुड़ी हों,तो मरीज के पास आधिकारिक जानकारी का विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध होगा। इससे अनौपचारिक दलाली की गुंजाइश कम की जा सकती है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब एनजीओस का चयन, वित्तीय पारदर्शिता शिकायत निवारण और स्वतंत्र ऑडिट भी उतनी ही मजबूती से लागू किए जाएं। साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर इस मॉडल की उपयोगिता और भी व्यापक हो सकती है।भारत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अस्पताल उपचार की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत किया है।लेकिन चिकित्सा बीमा या सरकारी उपचार सहायता और परिवार की गैर-चिकित्सकीय जरूरतें दो अलग -अलग प्रश्न हैं। इसलिए भविष्य की स्वास्थ्य नीति में उपचार खर्च के साथ 'पेशेंट एंड अटेंडेंट सपोर्ट सिस्टम, को भी जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार,मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में यदि प्रमुख सरकारी, निजी और धमार्दाय अस्पतालों के साथ स्थानीय एनजीओस का सुव्यवस्थित नेटवर्क तैयार किया जाए, तो बड़े महानगरों की ओर होने वाले अनावश्यक मरीज पलायन को कम किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग होगा और मरीजों को अपने राज्य में ही अधिक गरिमापूर्ण उपचार मिल सकेगा। साथियो यह मॉडल महानगरीय स्वास्थ्य संस्थानों पर दबाव कम करने की दिशा में भी उपयोगी हो सकता है। भारत में कुछ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों पर अत्यधिक मरीज भार रहता है। यदि राज्यों में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, कार्डियक संस्थान, मेडिकल कॉलेज और सक्षम धमार्दाय अस्पतालों को एकीकृत रेफरल नेटवर्क से जोड़ा जाए तथा मरीजों और तीमारदारों के लिए सहायता केंद्र विकसित किए जाएं, तो स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण संभव है। मरीजों को केवल इसलिए हजारों किमी दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उनके स्थानीय स्वास्थ्य तंत्र में जानकारी और समन्वय की कमी है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस अवधारणा की संभावनाएं महत्वपूर्ण हैं।

सहकारिता से कृषि तक: इफको की नई ऊंचाई

@ राष्ट्र समाज

भारतीय कृषि के बदलते परिदृश्य में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने प्रदर्शन से एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इफको ने इस वित्त वर्ष में 4,106 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। इफको के चेयरमैन दिलीप संघाणी ने इसे भारतीय सहकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। यह उपलब्धि केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों किसानों से जुड़े सहकारी मॉडल की बढ़ती ताकत का संकेत भी है। वित्त वर्ष के दौरान इफको ने 118 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद की बिक्री की। इससे कृषि क्षेत्र में उर्वरकों की आपूर्ति और सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व एक बार फिर सामने आया है।

नैनो खाद की ओर बढ़ता कदम

इफको की रणनीति अब पारंपरिक उर्वरकों तक सीमित नहीं है। नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिलीप संघाणी ने नई दिल्ली स्थित इफको सदन से पांच नैनो प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान देश के 19 राज्यों के 560 जिलों तक पहुंच रहा है।

इसके माध्यम से किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और नैनो जिंक जैसे उत्पादों के उपयोग और संभावित लाभों के बारे में जानकारी दी जा रही है। नैनो उर्वरकों को लेकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि में तकनीक का इस्तेमाल अब उत्पादन के साथ-साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग से भी जुड़ गया है। इफको के अनुसार, अब तक 218 लाख बोतल नैनो यूरिया प्लस की बिक्री हो चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि नैनो उर्वरकों ने भारतीय कृषि बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है।

इफको-एमसी में भी नई जिम्मेदारी

दिलीप संघाणी की भूमिका केवल इफको तक सीमित नहीं रही है। उन्हें इफको-एमसी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष भी चुना गया है। सहकारिता क्षेत्र में लगभग तीन दशक का अनुभव रखने वाले संघाणी का सार्वजनिक जीवन भी लंबा रहा है। वे अमरेली से चार बार सांसद रह चुके हैं। कृषि, सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों का यह अनुभव उनके नेतृत्व में इफको की प्राथमिकताओं में भी दिखाई देता है। एक ओर संगठन अपने वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तकनीक और नए कृषि उत्पादों को किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

केंद्र में महिला किसान

इफको की 55वीं वार्षिक आमसभा में महिला किसानों और सहकारिता में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी प्रमुखता मिली। संघाणी ने कहा कि वर्ष 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' घोषित किया गया है। इसी अवसर पर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि पहली बार दोनों बड़े सहकारिता पुरस्कार महिला नेताओं को प्रदान किए गए। भारतीय कृषि में महिलाओं की भूमिका अक्सर खेत और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित दिखाई देती है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं व्यापक है। खेती, पशुपालन, बीज संरक्षण, प्रसंस्करण और ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सहकारिता के मंच पर महिला नेतृत्व को सम्मान मिलना कृषि क्षेत्र में बदलती तस्वीर का संकेत है।

इफको की मौजूदा कहानी इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक साथ कई बदलाव दिखाई देते हैं रिकॉर्ड मुनाफा,118 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद की बिक्री, नैनो उर्वरकों का तेजी से विस्तार व महिला किसानों को बढ़ती प्राथमिकता। सहकारिता की ताकत को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ते हुए इफको जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल बन सकती है। आंकड़े उपलब्धि बताते हैं, लेकिन असली सफलता तब होगी जब इन पहलों का लाभ देश के खेतों और किसानों तक और अधिक व्यापक रूप से पहुंचे।

सत्य | समाज | राष्ट्र | समर्पण

एक जागरूक समाज, एक मजबूत भारत

राष्ट्र समाज

समाज की आवाज, राष्ट्र का विचार

विशेषांक
दिसंबर 2026
मूल्य : ₹ 100
पृष्ठ : 52

राष्ट्रतक न्यूज
राष्ट्र पहले, सदैव

महामना मालवीय और बाजपेयी

भारत के दो युगपुरुषों के जन्मोत्सव पर

एक विशेषांक

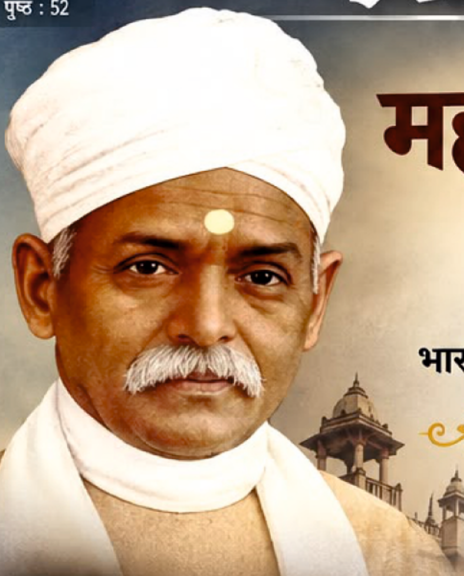

महामना
पं. मदन मोहन मालवीय
(25 दिसंबर 1861 – 12 नवंबर 1946)
"शिक्षा, चरित्र और राष्ट्रभक्ति ही भारत का भविष्य है।"

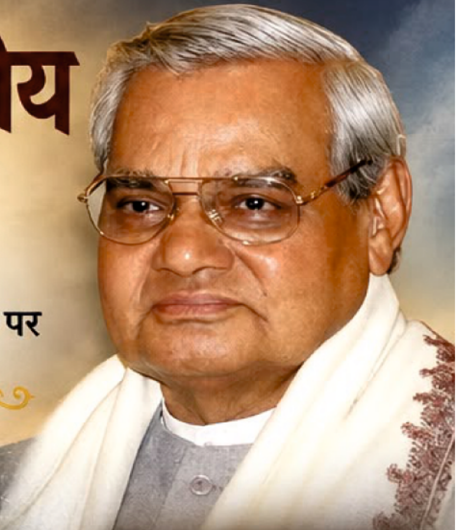

श्री अटल बिहारी बाजपेयी
(25 दिसंबर 1924 – 16 अगस्त 2018)
"छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।"

काशी हिन्दु विश्वविद्यालय

शिक्षा से संस्कार
लोकतंत्र से विकास
यही है भारत का मार्ग

- **महामना का जीवन और दर्शन**
  शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण
- **काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की गौरव गाथा**
  एक स्वप्न, जिसने भारत को दिशा दी
- **अटल जी का जीवन संघर्ष और राजनीति**
  कवि हृदय, दृढ़ नेतृत्व
- **अटल जी की विदेश नीति और वैश्विक पहचान**
  भारत की नई दिशा
- **दो युगपुरुष – एक दृष्टि**
  राष्ट्र प्रथम, राजनीति बाद में
- **विचार, प्रेरणा और आज की पीढ़ी**
  हम क्या सीखें?
- **विशेष लेख, संस्मरण, दुर्लभ तस्वीरें**
  इतिहास के पन्नों से

ऐसे ही महान व्यावक्तित्यों से
— बनता है —
नया भारत

"उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम एक समृद्ध, सशक्त और संस्कारवान भारत का निर्माण करें।"

डा. प्रमोद तिवारी
मुख्य संपादक
राष्ट्र समाज / राष्ट्रतक

ऐश्वर्य एवं वैराग्य का अद्भुत संगम है श्रीकृष्ण

@ राष्ट्र समाज

भगवान श्रीकृष्ण भारत की माटी, भारत की आत्मा और भारत के जनजीवन की धड़कन हैं। वे केवल आराधना के देवता नहीं, बल्कि जीवन को देखने की एक दृष्टि, संघर्षों से जूझने की प्रेरणा और भविष्य की ओर बढ़ने की दिशा हैं। वे ऐश्वर्य एवं वैराग्य का अद्भुत एवं निराला संगम हैं। श्रीकृष्ण के बिना भारतीय जीवन-दर्शन की कल्पना अधूरी है। जीवन के लगभग प्रत्येक आयाम-परिवार, समाज, राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, युद्ध, शांति, प्रेम, मित्रता, कर्तव्य, त्याग, नेतृत्व और आध्यात्मिकता में श्रीकृष्ण के विचारों और आदर्शों की छाप दिखाई देती है। इसीलिए जन्माष्टमी केवल श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीवन में उतारने का अवसर है। श्रीकृष्ण भारतीय संस्कृति के ऐसे अद्भुत एवं विलक्षण महानायक हैं, जिनके व्यक्तित्व में विरोधाभास दिखाई देने वाले अनेक गुण एक साथ समाहित हो जाते हैं। वे द्वारका के शासक हैं, लेकिन उन्हें सामान्यतः ह्यराजा श्रीकृष्णह्न नहीं कहा जाता। वे ब्रजनंदन हैं, नंदलाल हैं, कन्हैया हैं, माखनचोर हैं, गोपियों के चितचोर हैं और रासरचैया हैं। यही उनकी महानता है कि सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी वे जनमानस से कभी दूर नहीं हुए। उनका नेतृत्व राजमहलों तक सीमित नहीं था, वह गांवों की गलियों, ग्वाल-बालों, किसानों, पशुपालकों और सामन्य जन के हृदय तक पहुंचता था।

श्रीकृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि श्रेष्ठ नेतृत्व केवल अधिकार प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की कला है। उन्होंने सत्ता को कभी व्यक्तिगत सुख का साधन नहीं बनाया। समाज और राष्ट्र की व्यवस्था उनके लिए कर्तव्य थी और धर्म उनकी आत्मनिष्ठा। इसीलिए उन्होंने परिस्थितियों से पलायन नहीं किया। जहां प्रेम की आवश्यकता थी वहां प्रेम दिया, जहां मित्रता की आवश्यकता थी वहां मित्र बने, जहां संवाद जरूरी था वहां संवाद किया और जहां अधर्म का प्रतिकार आवश्यक हुआ वहां अत्यंत कठोर होकर सामने आए। यही संतुलन कुशल नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। आज प्रबंधन की दुनिया में निर्णय क्षमता, समय-प्रबंधन, संकट प्रबंधन, नेतृत्व, संवाद-कौशल, मनोविज्ञान और रणनीति को सफलता की अनिवार्य शर्त माना जाता है। इन सभी क्षेत्रों में श्रीकृष्ण का जीवन असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब मोह और मानसिक द्वंद्व से घिरकर अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि जीवन का विराट दर्शन दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म का मर्म समझाया-मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। यह संदेश आज भी हर विद्यार्थी, कर्मचारी, उद्यमी, प्रशासक, राजनीतिज्ञ और सामान्य व्यक्ति के लिए उतना ही उपयोगी है।

हमारी सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर कर्म से अधिक परिणाम की चिंता होती है। परिणाम की चिंता मन को भय, तनाव और असमंजस से भर देती है। श्रीकृष्ण का कर्मयोग इस मानसिक बोझ से मुक्ति का मार्ग देता है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, क्षमता और ईमानदारी से करना और परिणाम को व्यापक व्यवस्था पर छोड़ देना-यह जीवन-प्रबंधन का ऐसा सूत्र है जिसकी उपयोगिता कभी समाप्त नहीं हो सकती। श्रीकृष्ण की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी-स्थिर बुद्धि। शिशुपाल ने राजसूय यज्ञ की सभा में उन्हें लगातार अपमानित किया, फिर भी वे शांत रहे। दुर्योधन के दरबार में शांति-दूत बनकर गए और वहां भी उनका अपमान हुआ, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। इससे हमें सीख मिलती है कि उत्तेजना में लिया गया निर्णय प्रायः समस्या बढ़ाता है, जबकि शांत मन समाधान का रास्ता खोलता है। आधुनिक परिवारों से लेकर संसद, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक, यह प्रबंधन-सूत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है।श्रीकृष्ण केवल युद्धनीति के ज्ञाता नहीं थे, वे शांति के भी सबसे बड़े समर्थक थे। महाभारत का युद्ध उनकी पहली पसंद नहीं था। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब संवाद और न्याय की संभावनाएं समाप्त हो गईं, तभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग स्वीकार किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा करने की क्षमता है। सच्ची शांति वही है जिसके पीछे न्याय और आत्मबल की शक्ति हो। श्रीकृष्ण का सामाजिक दृष्टिकोण भी अत्यंत व्यापक था। उन्होंने ग्रामीण जीवन, गौ-संस्कृति, प्रकृति और सामुदायिक जीवन को सम्मान दिया। गोवर्धन प्रसंग हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामुदायिक एकता का संदेश देता है। माखन और दूध-दही के प्रसंगों को केवल बाल-क्रीड़ा के रूप में देखने के बजाय उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय संसाधनों की रक्षा का संदेश भी देखा जा सकता है। श्रीकृष्ण का लोकजीवन से जुड़ाव बताता है कि कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब उसकी विकास-यात्रा गांवों, किसानों, श्रमिकों और सामान्य नागरिकों को साथ लेकर चले। उनका व्यक्तित्व एक अद्भुत समन्वय है। वे अर्जुन के सारथी हैं और साथ ही विश्वरूप के दर्शन कराने वाले योगेश्वर। वे सुदामा के मित्र हैं और अत्याचारियों के लिए सुदर्शन चक्रधारी। वे बांसुरी की मधुरता हैं तो धर्मरक्षा के लिए आवश्यक कठोरता भी। वे प्रेम हैं, करुणा हैं, नीति हैं, रणनीति हैं, त्याग हैं और कर्म हैं। इसीलिए श्रीकृष्ण को किसी एक सीमा में बांधना उनके विराट व्यक्तित्व को छोटा करना होगा।

श्रीकृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का बहुआयामी विकास करना चाहिए। परंपरा में उनके द्वारा चौंसठ कलाओं के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। इसका व्यापक संदेश यह है कि शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। आज के समय में जब शिक्षा को केवल अंक, नौकरी और प्रतियोगिता तक सीमित करने का खतरा है, श्रीकृष्ण का जीवन हमें ज्ञान, कला, कौशल, सृजनशीलता और चरित्र के समन्वय की प्रेरणा देता है।

श्रीकृष्ण की राजनीति सत्ता प्राप्ति की राजनीति नहीं, बल्कि लोककल्याण और धर्मस्थापना की राजनीति थी। उनके जीवन में हमें यह सूत्र मिलता है कि सत्ता पर नैतिकता का अंकुश होना चाहिए और शक्ति का उपयोग जनहित के लिए होना चाहिए। आज भारत विकसित भारत के 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक शक्ति, विज्ञान, तकनीक, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक समरसता-हर क्षेत्र में भारत नई संभावनाओं की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में श्रीकृष्ण का दर्शन हमें बताता है कि विकास केवल भौतिक समृद्धि का नाम नहीं है। विकास तब सार्थक होगा जब उसमें चरित्र होगा, कर्तव्य होगा, करुणा होगी, न्याय होगा और अंतिम व्यक्ति के जीवन में भी आशा का प्रकाश पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की जो व्यापक यात्रा चल रही है, उसमें श्रीकृष्ण के कर्म, कर्तव्य, रणनीति, राष्ट्रहित और लोककल्याण के आदर्शों से प्रेरणा लेने की बड़ी संभावनाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय जीवन में भी श्रीकृष्ण का संदेश महत्वपूर्ण है। आज दुनिया संघर्षों, युद्धों, अविश्वास और शक्ति-संघर्षों से जूझ रही है। ऐसे समय में श्रीकृष्ण की नीति कहती है-पहले संवाद, फिर समन्वय और अंततः न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक शक्ति। भारत यदि विश्व में शांति, सह-अस्तित्व और मानवकल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है तो उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना के इस महान स्रोत से ऊर्जा लेनी होगी। श्रीकृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है। संघर्ष आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, प्रियजन दूर होंगे, संकट सामने खड़े होंगे, लेकिन मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि गीता का संदेश किसी एक युग, धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन गया है।

हनीमून पर कपूर खानदान की लाडली?

फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने बाकि सभी भाई बहनों से अलग फिल्मों और ग्लैमर की दुनिया से परे बेहद सिंपल लाइफ जीती है। अंशुला सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं और उनके पोस्ट भी इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो जाते हैं। अब एक बार फिर से अंशुला कपूर ने एक ऐसे पोस्ट कर दिया है जो कि काफी चर्चाओं में है। दरअसल, पोस्ट में अंशुला की कुछ मोनोकिनी वाली तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद फैंस का कहना है कि वो शादी के बाद पति रोहन ठक्कर के साथ हनीमून पर हैं।हालांकि आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, अंशुला सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कंटेंटफुल पोस्ट करती रहती है जिनसे तमाम लोग रिलेट करते हैं। ऐसा ही एक रियल लाइफ से जुड़ा एक ये पोस्ट ही। इस पोस्ट में अंशुला ने कमरे से लेकर वेकेशन की और भी तस्वीरें शेयर की हैं। अंशुला कपूर ने जुलाई में ही अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी की थी। इस ग्रैंड वेडिंग और रिसेप्शन में बी टाउन के तमाम सेलेब्स ने शिरकत की थी। अंशुला और रोहन की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उनकी बातचीत की शुरूआत एक ऐप के जरिए हुई थी, जो आजकल के जमाने में काफी आम है। यहीं से उनकी दोस्ती परवान चढ़ी और धीरे-धीरे एक-दूसरे के प्रति प्यार बढ़ा। दोनों ने लगभग ढाई साल तक एक-दूसरे को अच्छी तरह से समझा, हर सुख-दुख में साथ रहे और अपने रिश्ते को मजबूत किया। इस दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उनका प्यार और गहरा होता गया। आखिरकार, अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, अंशुला और रोहन ने सगाई कर ली है। अब बस इंतजार है उस शुभ घड़ी का, जब ये दोनों सात फेरे लेकर एक-दूजे के हो जाएंगे और कपूर परिवार में एक नए सदस्य का आगमन होगा! मस्कारा को लेकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों ने इसे अपनी रचनात्मकता के साथ अपनाया है। हर दिन मुझे इस गाने के नए-नए और अनोखे संस्करण देखने को मिलते हैं। अलग-अलग तरीकों से लोगों का इस गाने से जुड़ना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है।

बिग बॉस के 20वें सीजन में सलमान की बढ़ी डिमांड

सलमान खान एक बार फिर बिग बॉस के नए सीजन को होस्ट करने के लिए तैयार हैं। शो के ग्रैंड प्रीमियर से पहले सलमान खान की फीस को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान को बिग बॉस 20 के लिए करीब 120 करोड़ रुपये फीस मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस रकम की अभी तक सलमान खान या शो के मेकर्स की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में सलमान खान की बिग बॉस होस्टिंग फीस में काफी बढ़ोतरी हुई है। उनकी प्रति एपिसोड फीस करीब 2.5 करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात कही गई है। सलमान खान लंबे समय से बिग बॉस का चेहरा बने हुए हैं और हर सीजन में उनकी मौजूदगी शो के लिए बड़ा आकर्षण रहती है। ऐसे में नए सीजन को लेकर भी फैंस काफी उत्साहित हैं।

स्वरा भास्कर के गले की हड्डी बनी जौहर पर विवादित टिप्पणी

बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने साल 2018 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन पर टिप्पणी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। मामले पर स्वरा भास्कर ने एक क्लियरिफिकेशन वीडियो भी पोस्ट किया है लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर नेता स्वरा भास्कर के विरोध में उतर आए हैं। इसी बीच अब करणी सेना की तरफ से स्वरा भास्कर को धमकी दिए जाने का दावा सामने आया है। करणी सेना से जुड़े लोगों ने स्वरा भास्कर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और नारजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं करणी सेना की तरफ से स्वरा भास्कर को धमकी दिए जाने का दावा सामने आया है। करणी सेना महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष किर्ति राठौड़ ने स्वरा को भाषा सुधारने की नसीहत दी है। किर्ति राठौड़ ने कहा, 'स्वरा भास्कर पहले अपनी भाषा सुधारें। सनातन और हमारी वीरांगनाओं के बलिदान और शौर्य पर सवाल उठाने या आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। राजपूताना का इतिहास हमारी वीरांगनाओं के त्याग और साहस की गवाही देता है। जौहर को समझने के लिए उस दौर के इतिहास और परिस्थितियों को समझना जरूरी है।₹किर्ति राठौड़ ने आगे कहा, ₹अगर किसी प्रथा पर सवाल उठाना है, तो इतिहास और तथ्यों के आधार पर उठाइए। लेकिन हमारी वीरांगनाओं के बलिदान को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दीया मिर्जा का छलका दर्द

बॉलीवुड अभिनत्री दीया मिर्जा सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि स्टाइल आइकॉन भी हैं। दीया मिर्जा के लुक्स और उनकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। दीया मिर्जा ने पर्दे पर कई अलग अलग किरदारों को बखूबी निभाया है लेकिन साल 2001 में रिलीज हुई डेब्यू फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' उनका किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दीया मिर्जा अकसर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बात करती दिखाई देती हैं। एक बार दीया ने अपने करियर के अब तक के सबसे मुश्किल शूट के बारे में बात की। ये किस्सा जुड़ा है साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'तुमसा नहीं देखा' से। फिल्म में बार डांसर का किरदार निभा रही दीया मिर्जा ने 'मुझे तुमसे मोहब्बत है' गाने पर आइटम सॉन्ग किया था। गाना जबरदस्त हिट हुआ था। इसी गाने से जुड़ी याद शेयर करते हुए दीया मिर्जा ने बॉलीवुड बबल को बताया कि कैसे इस गाने को करने के बाद उनके अंदर का डर निकल चुका था। फिल्म में दीया एक बार डांसर के रोल में थीं और बार डांसर होने के चलते उन्होंने काफी बोल्ड कपड़ों में कई सारे मर्दों के सामने डांस किया था। दीया मिर्जा ने कहा, 'इस गाने ने मुझे उस डर से आजाद कराया, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये गाना परफॉर्म कर पाई, उसकी वजह वैभवी मर्चेंट थीं, जो उस गाने की कोरियोग्राफर थीं। उनके साथ उनकी टीम ने मुझे काफी कॉन्फिडेंट और सुरक्षित महसूस कराया। लेकिन, लड़की के तौर पर ये मेरे लिए अब तक की सबसे मुश्किल चीज थी।'

शालिनी पांडे का प्राइवेट वीडियो लीक

'अर्जुन रेड्डी' फेम शालिनी पांडे एआई वीडियो का शिकार हो गई हैं। प्राइवेट वीडियो के वायरल होते ही शालिनी पांडे ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर रिएक्ट किया है। शालिनी पांडे के रिएक्शन से साफ है कि वो इस वीडियो से पूरी तरह हैरान परेशान हैं। शालिनी पांडे इस वीडियो को शेयर-फॉरवर्ड-डाउनलोड ना करने की अपील की है। शालिनी पांडे ने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बयान जारी कर इस फर्जी वीडियो की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। एआई के गलत इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने लिखा कि वह अपने नाम से फैलाए जा रहे फर्जी एआई वीडियो पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। यह वीडियो पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इसमें वह बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति, खासकर महिलाओं को निशाना बनाने और नुकसान पहुंचाने के लिए तकनीक का इस तरह का दुरुपयोग देखना बेहद दुखद परेशान करने वाला है। अपने बयान में अभिनेत्री ने इस तरह के कंटेंट की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि तकनीक के ऐसे दुरुपयोग को कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। शालिनी ने अपने फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स से आग्रह किया कि यदि वे इस वीडियो को देखते हैं, तो इसे आगे शेयर, फॉरवर्ड या डाउनलोड न करें और न ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दें। इसके बजाय तुरंत उस कंटेंट की रिपोर्ट करें ताकि इसे और फैलने से रोका जा सके। उन्होंने सभी से एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने का अनुरोध किया। यह सीरीज उन पहलुओं को करीब से महसूस करने की कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि इसे देखने के बाद लोगों को सिर्फ अपनी अगली यात्रा की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी।

नेपाल तांडव पर फटा मनीषा कोइराला का कलेजा

नेपाल में भोटेकोशी नदी तंत्र में ग्लेशियर के गिरने से हुई त्रासदी के वीडियो हर किसी को डरा रहे हैं। पूरे नेपाल से तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। लाशों पर लाशे मिल रही हैं तो वहीं तमाम लोग अभी भी मलवे में लापता हैं। इस आपदा में नेपाली मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। मनीषा कोइराला ने लोगों से गुजारिश की है कि इस मुश्किल वक्त में देश के प्रति समर्थन जताएं। इस वक्त जब मनीषा का देश बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है तो उन्होंने लोगों से अपने देश में पर्यटन के लिए आने की अपील की है। उनका कहना है ऐसे में पर्यटन रुकना नहीं चाहिए। मनीषा कोइराला ने सद्गुरु द्वारा आयोजित एक विशेष सभा कार्यक्रम 'इन सॉलिडेरिटी विद नेपाल' में अपनी बात रखी। समाचार एजेंसी के मुताबिक, मनीषा कोइराला ने सद्गुरु के कार्यक्रम में देश के लिए समर्थन मांगा। अभिनेत्री ने कहा, 'मैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुजारिश करना चाहती हूं कि आपने नेपाल के प्रति बार-बार दया और प्यार दिखाया है।

आरईसी लिमिटेड को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में आरईसी लिमिटेड को वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के आधार पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। आरईसी को यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाइक, उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्य सभा सांसद श्री दिनेश शर्मा, लोकसभा सांसद सुरेश कुमार कश्यप तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल भी मौजूद थे। यह पुरस्कार आरईसी के सीएमडी जितेंद्र श्रीवास्तव, आई.ए.एस. ने प्राप्त किया।

यह विशेष गर्व का विषय है कि आरईसी ने यह सम्मान विद्युत क्षेत्र के सभी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा मंत्रालय से संबद्ध संगठनों में अर्जित किया है। यह उपलब्धि राजभाषा हिंदी के संवर्धन, प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति आरईसी की सतत प्रतिबद्धता और संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन, हिंदी में कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहन तथा नवीन पहलों के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में आरईसी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को इस सम्मान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। यह पुरस्कार पूरे आरईसी परिवार के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। यह पुरस्कार न केवल संगठन की उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करता है, बल्कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में आरईसी की अग्रणी भूमिका को भी रेखांकित करता है। 2 दिसंबर के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि एसीसी ने अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में संविदा आधार पर 7 दिसंबर, 2025 से एक और वर्ष की अवधि के लिए या नियमित पदाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लोक उद्यम विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दी जाने वाली शर्तों और नियमों के अनुसार होगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा नियुक्त लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य ओएनजीसी के नियमित अध्यक्ष की पहचान और चयन करना था। तीन सदस्यीय समिति के अन्य सदस्यों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव और पूर्व आईओसी अध्यक्ष बी अशोक शामिल हैं, जो एक प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञ हैं। पीईएसबी ने इस साल अप्रैल में सिंह के स्थान पर एक नियमित अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, क्योंकि उनका तीन साल का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त होने वाला था।

एनबीसीसी का सेशेल्स में 1008 घरों के निर्माण के लिए समझौता

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सेशेल्स गणराज्य सरकार के साथ ऑरोर द्वीप (इल ऑरोर) आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें सेशेल्स में संबंधित अवसंरचना सहित 1008 किफायती आवासीय इकाइयां शामिल हैं' महामहिम सेबेस्टियन पिल्लै, उपराष्ट्रपति, सेशेल्स गणराज्य और डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की गरिमामई उपस्थिति में बुधवार को इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते पर जोसेफ फ्रांस्वा, भूमि, आवासन एवं अवसंरचना विभाग के राज्य सचिव, सेशेल्स गणराज्य सरकार तथा श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (इंजी.), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना सेशेल्स में संबंधित अवसंरचना सहित 1008 किफायती आवासीय इकाइयों के विकास की परिकल्पना करती है, जिसका उद्देश्य शहरी जीवन-स्तर में सुधार करना तथा संधारणीय विकास को संवर्धित करना है। इस परियोजना को भारत के निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा प्रदान की गई 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

परियोजना के कार्यक्षेत्र में समर्पित सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र (एसटीपी) सहित आवश्यक संबद्ध अवसंरचना कार्यों का निर्माण भी शामिल है, जिससे ऑरोर द्वीप पर संधारणीय एवं आधुनिक सामुदायिक जीवन-स्तर सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना से सेशेल्स में आवास की उपलब्धता में सुधार लाने और संधारणीय शहरी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

यह कार्यनीतिक सहयोग एनबीसीसी के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलियो में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और बड़े पैमाने पर आवास और अवसंरचना परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में कंपनी की विशेषज्ञता को रेखांकित करता है। यह विदेशों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना समाधान प्रदान करके भारत की विकास साझेदारियों में योगदान देने के लिए एनबीसीसी की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

Haldiram's
Banao
CHATPATE
PAL AUR
MEETHI
Yaadein!
TRADITION IN EVERY BITE,
HAPPINESS IN EVERY MOMENT.
Crafted with the finest ingredients and authentic recipes.
A perfect blend of savoury snacks and traditional sweets.
Hygienically prepared and packed for your safety.
Loved by millions for generations.
Perfect for every occasion, celebration and craving.
Bringing joy, taste and togetherness to your everyday moments.
From our kitchen to your heart – the Haldiram's promise.
REAL INGREDIENTS. GREAT TASTE. TIMELESS TRADITION.
Taste the tradition. Share the happiness.!
Shop Online @ www.haldiramsonline.com

RNI No.: DELHIN/2014/56304

राहत टैक्स से फ्रीडम इंटरेस्ट से

नागरिकों के लिए सुनहरा मौका

अवधि
15 अगस्त से
15 दिसंबर,
2026 तक

नगर निकायों में लंबित संपत्ति कर
(गृहकर/जलकर/सीवर-कर) हेतु

एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.)

पूरा बकाया भुगतान करने पर ब्याज एवं सरचार्ज में मिलेगी
100% छूट

ऑनलाइन तथा ऑफलाइन
दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा

बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए
अधिकतम **3 किस्तों** की सुविधा

बकाया राशि का **1/3 हिस्सा** 30 दिनों में और शेष **2/3 हिस्सा**
दो मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा

1 अप्रैल, 2026 तक लंबित सभी प्रकार की
संपत्तियों के कर पर मिलेगा **OTS का लाभ**

**अपने नगर निकाय के कार्यालय आएं,
समय रहते OTS का लाभ उठाएं,
कर के बोझ से मुक्ति पाएं.**

OTS अपनाएं
ब्याज में
पूरी राहत पाएं

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

nagarvikas_up UPNagarVikasVibhag NagarVikas_UP @NagarVikasVibhagUP

टोल फ्री नं. : 1533